अज्ञात वक्ता: देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज दोपहर आयोजित किए जा रहे इस सत्र में हमारे साथ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने फोन साइलेंट मोड पर डाल लें। धन्यवाद। भारतीय वैश्विक परिषद की तरफ से मुझे, हमारे जाने- माने विद्वानों वाले पैनल के साथ "ट्रंप 2.0 के एक वर्ष: पुनः नियोजन या दरार" विषय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

इस चर्चा की अध्यक्षता और संचालन प्रोफेसर सी. राजा मोहन करेंगें। श्री मोहन जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्टडीज में विशिष्ट प्रोफेसर हैं। पैनल के अन्य सदस्य हैं- कार्नेगी इंडिया में सिक्योरिटी स्टडीज़ प्रोग्राम के अध्येता श्री दिनाकर पेरी, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अटलांटिक काउंसिल में रेजिडेंट सीनियर फेलो, साउथ एशिया- डॉ. माइकल कुगेलमैन। मणिपाल अकैडमी ऑफ हायर एजुकेशन में भू-राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग की अध्यक्ष प्रो. के. पी. विजयालक्ष्मी और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. पंखुरी गौर।

चर्चा के बाद प्रश्नोत्तर सत्र होगा, जिसका संचालन अध्यक्ष महोदय करेंगे। अब मैं प्रोफेसर राजा मोहन से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना आरंभिक भाषण दें और कार्यवाही शुरू करें। धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: आप सभी का धन्यवाद और आज दोपहर की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज दोपहर यहाँ तक आना आसान नहीं था, ट्रैफिक बहुत था, इसलिए आप सभी का सच में स्वागत है। हमारे साथ आज दो प्रतिभागी ऑनलाइन भी होंगे। आज के विषय की एक अच्छी बात यह है कि इसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। बीते एक वर्ष से, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, वह है राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शासन के दूसरे कार्यकाल में जो जबरदस्त उथल- पुथल मचाई है। तो एक वर्ष लगभग सौ साल जैसा लगता है, जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं, और जब हम बात कर रहे हैं, तब भी शायद कुछ- न- कुछ बदल रहा होगा।

मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं पैनल के चारों सदस्यों से भी अनुरोध करूँगा कि वे इस विषय की कुछ जानकारी पहले से स्वीकार कर लें क्योंकि मुझे लगता है कि हममें से हर कोई अपने-अपने तरीके से इन मुद्दों से जुड़ा हुआ है। इसलिए, सीधे उन खास मुद्दों पर आते हैं जिनके बारे में आप हर कोई दस- दस मिनट बात करना चाहता है। तो आरंभिक भाषण में मैं केवल चार बातें कहूँगा।

पहली, मुझे लगता है कि बदलाव स्टाइल और वास्तविकता दोनों में है। इसलिए, जिन कई नीति मुद्दों पर हम बात करते हैं, उनमें आज ट्रंप ऐसे आज़ाद और बेफिक्र हैं, जैसे अमेरिका का कोई भी पिछला राष्ट्रपति नहीं रहा, न तो घरेलू राजनीतिक दबावों से, न अपनी पार्टी से और न ही स्थायी विदेश नीति व्यवस्था से। यह सच में अमेरिका के इतिहास में अनोखा पल है। हमें देखना होगा कि यह सब कैसे होता है लेकिन यह स्टाइल, पर्सनल, लगभग एकतरफ़ा और बिना किसी रोक- टोक के, न तो विधायिका से, न अपनी राजनीतिक पार्टी से और न ही मीडिया से, यह अमेरिका के इतिहास में एक बहुत ही कमाल का पल है, यदि आप केवल अमेरिका को देखें।

दूसरा, मुझे लगता है कि एक तरफ दोस्तों और सहयोगियों और दूसरी तरफ दुश्मनों के साथ संबंध, दोनों में बदलाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वह केवल अपने दुश्मनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं बल्कि वह अपने दुश्मनों के साथ अधिक अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, यदि आप चाहें तो कह सकते हैं, केवल दो देश जिनके प्रति उसने कुछ सम्मान और इज़्जत दिखाई है, वे हैं रूस और चीन लेकिन बाकी मामलों में वे एक ही तरह से सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने वाले हैं, ऐसी बातें कह और कर रहे हैं जो आपको नाराज़ कर सकती हैं। यह समझना ज़रूरी है कि इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। मनोविश्लेषण करना सरल है, ट्रंप के

बारे में जो भी मनोप्रलाप चल रहा है। मुझे लगता है कि यह उन नीतियों के बारे में है जिन पर वह और उनके समर्थक विश्वास करते हैं और उनका दूसरों पर क्या प्रभाव होता है?

जब भारत में लोग सोचते हैं कि एच-1बी (H-1B) हमें टारगेट कर रहा है, तो देखिए, यह बहस आव्रजन के खिलाफ है। लेकिन हाल के सबसे बड़े अप्रवासी समुदायों में से एक होने के नाते, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक दिखता है और अमीर है, आप इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसे भारत पर हमला समझना चाहिए। बल्कि यह सवाल है कि आप किसी समाज में आव्रजन से कैसे निपटते हैं। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा मुद्दा था। इसलिए, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका में क्या बदल रहा है। बाकी विश्व के बारे में अमेरिका का नज़रिया, मुझे लगता है कि यही वह बुनियादी बदलाव है जो हो रहा है।

ट्रंप ने आव्रजन, गठबंधन, वैश्वीकरण और बहुपक्षीय संस्थानों के खिलाफ़ लंबे समय से चली आ रही नाराज़गी को आवाज़ दे दी है। आज हम यही देख रहे हैं कि वह नाटो (NATO) के साथ संबंध समाप्त करने को तैयार हैं, जब कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनसे पूछा था कि क्या ग्रीनलैंड लेने और नाटो खोने के बीच कोई विकल्प होगी? उन्होंने कहा था, हाँ, एक विकल्प है जिस पर वो विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि वह नाटो खोने के डर से पीछे हट रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको उस बदलाव का पैमाना और गंभीरता समझनी होगी जो वह सामने ला रहे हैं।

चौथा मुद्दा, मुझे लगता है कि सभी बहुपक्षीय संस्थानों के बारे में, यदि आपको लगता था कि डब्ल्यूटीओ भगवान है तो माफ करिए ट्रंप ऐसा नहीं सोचते। उन्हें नहीं लगता कि यह सच में इंसान का बनाया हुआ साधन है, और यदि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए काम नहीं करता है तो वे इसका विघटन कर देंगे। उन्होंने बीते एक वर्ष में आपको दिखा दिया है कि डब्ल्यूटीओ या संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कुछ भी रक्षणीय नहीं है। लेकिन अमेरिकी राजनीति में हमेशा एक ऐसा धड़ा रहा है जो संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करता था हालांकि अमेरिका ने ही बड़े पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र को बनाने में नेतृत्व किया था, फिर भी हमेशा बहुत अधिक शक था, विशेषरूप से रिपब्लिकन पार्टी में। आज, ट्रंप ने इसे अगले स्तर पर ले जाकर सच में एक नया शांति बोर्ड बनाया है, जिसके बारे में मेरा मानना है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो कल दावोस में घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

तो आप में वास्तव में हिम्मत है, आप इसे लापरवाही कह सकते हैं, आप इसे बेवकूफी कह सकते हैं, आप इसे महत्वाकांक्षा कह सकते हैं कि जो बदलाव प्रस्तावित किया जा रहा है, मुझे लगता है, वह सच में बहुत बड़ा है। इसलिए, हमारे लिए यह केवल भारत- अमेरिका तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अमेरिका को, अमेरिका में बदलाव के स्रोत को और यह सब कैसे होगा, इसे और गहराई से समझने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज दोपहर की यह चर्चा शानदार होगी और हमारे साथ चार बेहतरीन विशेषज्ञ भी हैं।

हमारे साथ के.पी. विजयालक्ष्मी, पुरानी दोस्त, मणिपाल से हैं। माइकल कुगेलमैन, जो मुझे लगता है दावोस में ही हैं, नहीं तो वाशिंगटन, उनके निवास स्थल में उनके लिए यह समय अल-सुबह का होता। हमारे साथ कार्नेगी, भारत से दिनाकर पेरी हैं और फिर हमारे साथ हैं पंखुड़ी गौर। मैं क्या कह रहा हूँ, हम दिनाकर से शुरू करते हैं, लेकिन हममें से हर कोई अपनी बात दस (10) मिनट की समय- सीमा का ध्यान रखते हुए पूरा करेगा। इसलिए कृपया अपनी प्रस्तुति को छोटा और संक्षिप्त रखें ताकि हमारे पास सवाल- जवाब के लिए अधिक समय रहे। मैं अब अपनी बात खत्म करता हूँ और चर्चा में आगे बढ़ते हुए, जी हाँ, मुझे लगता है कि अब आप अधिक साफ़- साफ़ देख सकते हैं।

दिनाकर पेरी: आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले, माफ़ करें, जैसा कि सर ने बताया, दिल्ली में इस समय ट्रैफिक की समस्या बहुत गंभीर हो चली है और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसलिए, वास्तव में एक कार्यक्रम से दूसरे

कार्यक्रम के लिए भागना पड़ रहा है। इसी बात पर, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। सिद्धि, धन्यवाद। आईसीडब्ल्यूए में एक बार फिर से आना बहुत अच्छा लग रहा है।

जल्दी से, मैं कोशिश करूँगा कि हम चर्चा कर सकें, उससे पहले ही इसे समाप्त कर दूँ। एकालाप से संवाद हमेशा ही बेहतर होता है। इसी बात पर, मेरे कहने का अर्थ है, हम सब जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, हम बहुत करीब से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो, व्यापार सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। यह कहना कि व्यापार गलत होगा क्योंकि यह व्यापार का मुद्दा नहीं है। यह प्रशुल्क यानी टैरिफ के बारे में नहीं है। यह टैरिफ के बारे में है। आप ट्रंप को कैसे मनाएंगे? यही वह मुद्दा है जो 10 मई को खराब हो गया था। यानि, समय में थोड़ा पीछे लौटिए। अप्रैल में, हम सभी को बताया गया था कि डील तैयार है। एक रूपरेखा पर सहमति बनी थी। रियायतें दी गईं, भारत ने बहुत सारी रियायतें दीं। यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र में भी, मोटे तौर पर। मुख्य बातों पर सहमति बन गई थी। सब कुछ ठीक था। और अचानक, जैसे ही ऐसा होता है, 10 मई को, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, वह एक ट्वीट। भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। भारत ने कहा, ठीक है, अमेरिका इसमें मध्यस्थ नहीं होगा और सब कुछ बिखर गया।

बीते कुछ सप्ताहों में कुछ खुलासे हुए हैं कि नेपथ्य में क्या हुआ था। यह सब उसी तरफ संकेत करता है। लेकिन बात यह है कि यह केवल व्यापार के बारे में नहीं है। मुद्दा कहीं और है। अभी भी सवाल यह है कि उस समस्या को कैसे ठीक किया जाए? तो, इन सब में, अब रक्षा की बात कर लेते हैं। इन सभी बड़े मुद्दों में, रक्षा अभी सबसे सशक्त स्तंभ रहा है। बीते एक वर्ष में, रक्षा ने मोर्चा संभाला हुआ है। क्यों? देखिए कितने सारे कार्य हो रहे हैं। अभ्यास, वचनबद्धता, यहाँ तक कि कुछ सैन्य खरीद भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ आपातकालीन खरीद भी की गईं। जैसे, जेवलिन एंटी- टैंक गाइडेड मिसाइलों के बाद यह सबसे बड़ी खरीद में से एक है।

भारत ने यह सिस्टम पहले नहीं खरीदा था। इसका परीक्षण किया गया, आज़माया गया। इसमें कई बदलाव हुए हैं। भारत ने हाल ही में जाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। कम मात्रा में, लेकिन फिर भी, भारतीय सेना के लिए यह एक नया समावेशन है। अब यह हो चुका है। एमएस- 60 (MS-60) रोमियो के लिए कुछ समर्थन पैकेज भी हैं। इस तरह की कई चीजें हुई हैं। यह सब हुआ है। मेरे कहने का अर्थ है, यह रुका नहीं है। पी- 8 (P-8) का आदान- प्रदान हुआ है। बड़े सैन्य अभ्यास हुए हैं। उन सब में कोई रुकावट नहीं आई है। यहाँ तक कि बड़े सौदों की बात करें तो कुछ गलतफहमियों को दूर करने के लिए, बहुत कुछ लिखा गया है कि बड़े रक्षा सौदे रोक दिए गए हैं, जो कि गलत होगा।

क्यों? क्योंकि इन सौदों में वास्तव में बहुत समय लगता है। जब यह सोच- विचार चल रहा था, टीमें यहाँ आईं, बातचीत की, और फिर लौट गईं। यह आना- जाना होता रहा है। फिर से पी8I (P8I) सौदा इसका एक उदाहरण है। टीमों का आना- जाना कई बार हुआ। अभी भी यह उस चरण पर नहीं है जहाँ भारत अमेरिका को अनुरोध पत्र जारी कर सके। एक प्रक्रिया होती है। और नौकरशाही हर जगह है। इसमें समय लगता है। यह सब भी चल रहा है।

फिर, इसमें एक बात गड़बड़ हो गई, वह है स्ट्राइकर सौदा। स्ट्राइकल सौदा इस झगड़े की वजह से नहीं रुकी है। यह दूसरे कारणों से रुक गई है। स्ट्राइकर एक बख़्तरबंद सैनिक वाहन (आर्मर्ड पर्सनल कैरियर) है। माफ़ करें, मैं रक्षा प्रवाह से भटक गया। तो बख़्तरबंद सैनिक वाहन, जिसे अमेरिका ने भारत को सह- विकास या सह- उत्पादन में से एक के रूप में पेश किया है, सह- विकास नहीं बल्कि सह- उत्पादन। एमक्यू-9 (MQ-9), यूएवी (UAV's) जो वायु क्षेत्र के लिए है, यह थल क्षेत्र के लिए- थल, समुद्र, हवा के लिए है। वे तीनों ही के लिए सह- उत्पादन पहल चाहते थे।

तो स्ट्राइकर वहाँ था। अच्छी बात है, बढ़िया मंच। लेकिन समस्या यह थी कि यह असल में भारतीय सेना की ज़रूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठता। बीएमएल (BML) द्वारा इसे भारत में असेंबल करने के लिए बातचीत हुई। बहुत चर्चा की गई। लेकिन सितंबर 2024 में समस्या आ गई। समस्या यह है कि यह जल और थल दोनों पर नहीं चल सकता यानि यह एम्फीबियस नहीं है। इसमें एकीकृत जैवलिन या एटीजी (ATG) नहीं लगा। ये कुछ मुख्य समस्याएं हैं। इसलिए सौदा अटका हुआ है, न कि ट्रंप या व्यापार सौदे की वजह से। इन दोनों को अलग- अलग समझना चाहिए।

तो कुल मिलाकर थोड़ी- बहुत बातचीत चल रही है। क्वाड पर एक ज़रूरी बात। अब आप क्वाड को कई प्रकार से समझ सकते हैं क्योंकि इसके दायरे में सब कुछ आता है। आप किसी भी क्षेत्र का नाम लें, वह क्वाड के अधीन आता है। लेकिन कुल मिलाकर, अभी भी उम्मीद है। शिखर सम्मेलन अभी नहीं हुआ है, फिर भी हर तरफ आशा है और ऐसा होना सही भी है क्योंकि, एक तो, अमेरिका क्वाड में कोई धन नहीं लगाता, जो सबसे सुरक्षित बात है। दूसरा, साझीदार देश असल में अपने- अपने क्षेत्र में क्षमताओं को विकसित करने के लिए पैसा लगा रहे हैं। वास्तव में अमेरिका के लिए भी यह अच्छा है, बोझ बांटना, जैसा कि एनएसएस कहता है और ट्रंप भी दोहराते रहे हैं।

इन सब चीजों में, रक्षा एक मज़बूत सहारा रहा है। लेकिन क्या हम बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे? यह एक सवाल है जो मुझसे बार- बार पूछा जाता है। मुझे नहीं लगता। हम प्रक्रिया तक पहुँचेंगे। हम प्रक्रिया पूरा करेंगे। हस्ताक्षर करना एक राजनीतिक निर्णय होता है। देखिए, बड़े- बड़े सौदों में, हस्ताक्षर करना हमेशा एक राजनीतिक फैसला होता है। कब, कैसे, किस प्रारूप में। शायद यह तब तक चलेगा जब तक कोई व्यापार सौदा अंतिम रूप नहीं ले लेता या कोई समझौता नहीं हो जाता। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है।

लेकिन, यदि केवल रक्षा या सुरक्षा सहयोग की बात करें, तो यह कैसा रहेगा? बस दो मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। हम कह सकते हैं कि यह बस थोड़े समय की बात है। शायद हाँ। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठीक है तीन और साल, ट्रंप चले जाएंगे, स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि, क्या वे होंगी? देखिए, ट्रंप कोई अकेला कारण नहीं हैं, वह एक बड़े रुझान का नतीजा हैं, जो पूरे विश्व में हो रहा है। बस ऐसा हुआ है कि वह विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, इसलिए हालात ऐसे हैं।

ट्रंप के बाद कौन आएगा? व्यवस्था पूरी तरह से पूर्ववत नहीं होगी। एक बार जब नए मानदंड निर्धारित हो जाते हैं तो यह पूरी तरह से वापस नहीं होता। यह कहीं बीच में होता है। हम अपने बचाव के लिए किस तरह तैयारी करें? हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। निर्भरता के बारे में एक ज़रूरी बात, जो हमारे पास हो सकती है। जैसे, भारत ने बहुत लंबे समय तक अमेरिका से कोई भी हमला करने वाला सैन्य मंच नहीं खरीदा है। केवल अपाचे और एम777 हॉवित्ज़र (M777 howitzers), अपाचे हेवी अटैक हेलीकॉप्टर और एम777 (M777) अल्ट्रा- लाइट हॉवित्ज़र। ये दोनों पहले ऐसे हमलावर हथियार थे जिन्हें भारत ने असल में अमेरिका से खरीदा था। अब हमारे पास इनकी पूरी श्रृंखला है। भारत अभी भी अमेरिका से लड़ाकू जेट खरीदने से बचता रहा है।

लेकिन, अब इसकी एक नई सच्चाई है। अब से 10 वर्ष या 15 वर्ष में, भारतीय वायु सेना का लगभग आधा या कम- से- कम 40% लड़ाकू बेड़ा अमेरिकी इंजन से चलेगा। यह बहुत अधिक निर्भरता है। आप इसे सकारात्मक रूप से देख सकते हैं, आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। हमें नहीं पता। हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। आपके एलएसी, हल्के लड़ाकू विमान, मार्क 1, मार्क 1 अल्फा, मार्क 2. सभी जीई (GE) इंजन वाले, जनरल इलेक्ट्रिक, एफ404 (F404), एफ414 (F414) प्रकार के। फिर वही, वही कंपनी, अमेरिकी इंजन। यह आपके पांचवीं (5) पीढ़ी के भविष्य के एएमसीए (AMCA) भारत के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी शक्ति देगा। शुरुआती खेप में सभी में अमेरिकी इंजन होंगे।

तो यह लगभग 400 लड़ाकू विमान के करीब हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है। हम संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। अब यह थोड़ी उथल- पुथल और वास्तविकता की पड़ताल का सवाल है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद, दिनाकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिनाकर कई वर्षों से ***द हिंदू*** के लिए रक्षा विषय पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसलिए उन्हें वास्तव में बहुत जानकारी है। इस परिचय के लिए धन्यवाद दिनाकर। मैं बस ये देख रहा हूँ कि माइकल ऑनलाइन जुड़े हैं या नहीं। माइकल कुगेल, क्या आप ऑनलाइन हैं?

माइकल कुगेलमैन: जी हाँ, मैं ऑनलाइन हूँ। आशा है, आप सब को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद, माइकल। तो आपके पास भी अपने विचारों को साझा करने के लिए 10 मिनट का समय है। आपने बीते कुछ सप्ताहों में भारत, अमेरिका, अमेरिका और दक्षिण एशिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसलिए कृपया अपने विचार 10 मिनट की समय- सीमा में हमसे साझा करें।

माइकल कुगेलमैन: बिल्कुल, बहुत- बहुत धन्यवाद। कैमरा बंद होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं दावोस में हूँ और दिलचस्प बात यह है कि यहां सिग्नल थोड़ा कमज़ोर है। इसलिए अपनी आवाज़ धाराप्रवाह आप सब तक पहुँचाने के लिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया है। आशा है मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही होगी। मैंने सोचा कि मैं इस सवाल पर कुछ मिनटों के लिए बात करूं, जिसेक बारे में मुझे लगता है कि हममें से बहुत से लोग सोच रहे हैं। वह यह है कि ट्रंप 2.0 में अमेरिकी विदेश नीति को कौन संचालित कर रहा है? मेरा मानना है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पी (P), तीन पी (P) पर निर्भर करता है। पहला है -पॉलिसी (नीति)। राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति एक मज़बूत, आक्रामक नहीं भी तो व्यावसायिक एवं लेन-देन वाला है। यह ट्रंप के पहले कार्यकाल की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक है।

इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका की विदेश नीति पूरी तरह से ऐसा कदम उठाने पर ध्यान दे रही है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अमेरिका के आर्थिक हितों की रक्षा हो और उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। यही वजह है कि ट्रंप की विदेश नीति की मुख्य प्राथमिकताओं में प्रशुल्क (टैरिफ) लगाना और महत्वपूर्ण खनिजों को हासिल करना शामिल है, जिसमें परंपरागत अमेरिकी रणनीतिक हितों और महत्वपूर्ण साझेदारियों पर पड़ने वाले असर की अधिक परवाह नहीं की जाती। इसलिए, इसके कुछ अजीब, यदि बिल्कुल ही अजीब नहीं तो, नतीजे निकलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत जैसे अमेरिका के करीबी साझीदार पर 50% प्रशुल्क (टैरिफ) लगा दिया गया था, क्योंकि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था और क्योंकि भारत व्यापार वार्ता में अमेरिका की सभी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं था।

राष्ट्रपति ने, ज़ाहिर है, इसके आवश्यक खनिजों और कुछ दूसरी वस्तुओं की वजह से ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की धमकी दी है। अमेरिका ने नशीले पदार्थों (ड्रग्स) और ऊर्जा पर मादुरो की नीति एवं अमेरिका पर उसके असर की वजह से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वेनेजुएला पर हमला किया। दूसरी अहम बात, जिसे मैं बताना चाहूँगा, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी विदेश नीति को चला रहा है और चलाता रहा है, वह है उनका व्यक्तित्व। मेरे कहने का मतलब है, इस बारे में बहुत चर्चा की गई है। उनका व्यक्तित्व ऐसा है जो हाल के इतिहास की अहमियत और रणनीतिक हितों की अहमियत को नज़रअंदाज़ करती है। यह असल में इस सवाल पर अधिक फोकस था कि तुमने हाल ही में मेरे लिए क्या किया है?

सच कहूँ तो, यह बात भी स्पष्ट है और हम यह जानते हैं कि ऐसा ही है। उनका व्यक्तित्व पहचान, तारीफ़ और सत्यापन की गहन आवश्यकताओं से चलती है। और इसलिए इससे ज्यादा अजीब और असामान्य नतीजे निकलते हैं। नाटो (NATO) गठबंधन को धमकियाँ दी जाती हैं। विदेशी नेता जो ट्रंप की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, वे उनकी चापलूसी करते हैं, जबकि जो लोग उनकी चापलूसी नहीं करते, वे उन्हें नाराज़ कर देते हैं।

तीसरा पी (P) जिस पर मैं ज़ोर देना चाहूँगा, जो ट्रंप के दूसरे शासनकाल में अमेरिका की विदेश नीति को समझने में मदद करता है, वह है कर्मचारी विभाग (पर्सनेल/ personnel)। अपने पहले कार्यकाल के उलट, राष्ट्रपति ने अपने शासन में वफादारों को ही जगह दी है, जिसका मुझे लगता है कि यह असर हुआ है कि उनकी विदेश नीतियों के खिलाफ विरोध की संभावना कम हो गई है और उनकी विदेश नीतियों पर नियंत्रण और संतुलन भी सीमित हो गए हैं। इसलिए यह सुनिश्चित हो जाता है कि उनकी विदेश नीति योजना के सबसे कट्टर, सख्त तत्वों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी जैसा कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान कुछ मामलों में हुआ था।

साथ ही, मुझे लगता है कि यह विशेष रूप से आवश्यक है, अमेरिकी विदेश नीति अब ह्वाइट हाउस चला रहा है, न कि अंतरएजेंसी प्रक्रिया में काम करने वाली नौकरशाही। और ह्वाइट हाउस में, जो लोग ह्वाइट हाउस के भीतर विदेश नीति चला रहे हैं, उनमें ताकतवर कट्टरपंथियों का एक छोटा समूह है, जिनमें से कुछ, शायद उनमें से कई विदेश नीति के विशेषज्ञ नहीं हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भूमिका को बहुत कम कर दिया गया है। नतीजतन, अमेरिकी सरकार में जो लोग अमेरिका के रणनीतिक हितों की अहमियत को वास्तव में समझते हैं, और जो लोग भारत जैसे महत्वपूर्ण साझीदार के साथ अमेरिका के संबंधों के संदर्भ को समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं, उन्हें किनारे कर दिया गया है। फिलहाल वे नीति को संचालित करने या उसे प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं।

अब, यदि हम देखें और यदि अमेरिकी सरकार की नौकरशाही में मध्यम- स्तर के अधिकारियों और विशेषज्ञों को, बड़े अंतरएजेंसी समुदाय में, विदेश नीति पर प्रभाव डालने या उसका संचालन करने के लिए अधिक अधिकार दिए जाते हैं, तो आप ट्रंप की विदेश नीति में कुछ नरमी देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका- भारत संबंध को वापस पटरी पर लाने के लिए बेहतर प्रयास शामिल हैं।

अपनी बात पूरी करने से पहले, मुझसे कहा गया था कि मै इस बारे में थोड़ी चर्चा करूँ कि यहाँ के लोग अभी अमेरिका में नहीं हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग ट्रंप की विदेश नीति को किस तरह से देखते हैं। स्पष्ट है, मैं बहुत सारे अलग- अलग विचारों को एक जैसा नहीं बताना चाहता। स्वाभाविक रूप से, उनके आलोचकों को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके समर्थकों को यह आम तौर पर पसंद है। कैपिटल हिल पर, बेशक, कई डेमोक्रेट्स ने आलोचना की है। कुछ रिपब्लिकन शायद उनकी कुछ, यदि अधिक नहीं तो, नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन वे ज्यादातर चुप रहे हैं। मेरा मानना है कि ट्रंप के लिए देश में घरेलू राजनीतिक जोखिम हो सकते हैं, इस बात को लेकर कि उनके कुछ समर्थकों ने उनकी विदेश नीति पर कैसी प्रतिक्रिया दी है और इस वर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए वे आगे कैसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

उदाहरण के लिए, पश्चिममध्य और मैदानी इलाकों के रिपब्लिकन राज्यों में कुछ किसान हैं जिन्हें ट्रंप के अमेरिकी मदद और विदेशी सहायता को खत्म करने से नुकसान हुआ है क्योंकि इनमें से कई किसान ऐसी फसलें उगा रहे थे जो अमेरिकी खाद्य सहयोग कार्यक्रम का हिस्सा थीं। दूसरी बात, ट्रंप के कई समर्थकों ने युद्ध पर्यटन में शामिल न होने के उनके वादे पर भरोसा किया और उसे समर्थन दिया लेकिन फिर वेनेजुएला का मामला आया और कौन जानता है कि आगे ईरान में क्या हो सकता है और शायद दूसरे देशों में भी।

आखिर में, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ नीतियां लाईं हैं, उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुँचाया है लेकिन हमने अमेरिका में आर्थिक तनाव के कुछ संकेत देखे हैं, विशेषरूप से जब बात महंगाई और खाने- पीने की चीजों की महंगाई की आती है। किराने की दुकानों पर जाने वाले लोगों ने कीमतों में वृद्धि देखी है। मुझे लगता है कि इसका उन पर राजनीतिक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि उनकी विदेश नीति बहुत अलग और अतिवादी है। जिस बात पर वह विश्वास करते हैं, वह मध्यावधि चुनावों के समय उनके लिए राजनीतिक रूप से महंगी पड़ सकती है। धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद माइकल। बहुत ही सटीक प्रस्तुति के लिए। मुझे लगता है कि ये तीन पी (P) हमारे लिए बहुत उपयोगी है, विशेषरूप से हम जैसे लोगों के लिए जो बाहर से विचार कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आम तौर पर अमेरिका को एक ब्लैक बॉक्स, एक अकेली, एक जैसी चीज़ समझने की प्रवृत्ति होती है और असल में अंदरूनी बदलाव एवं संरचना कैसे मायने रखती है और वे भीतर- ही- भीतर कैसे बदल रहे हैं और अमेरिका के बाहरी संबंधों पर उनका क्या असर होता है। अब मैं एचडीआईआर की प्रोफेसर डॉ. विजयालक्ष्मी का रुख करूँगा, क्या आप मात्र 10 मिनटों में अपने विचार साझा कर सकती हैं और हाँ उसके बाद हमारे दिलचस्प दर्शकों की बारी आएगी।

के. पी. विजयालक्ष्मी: राजा, बहुत- बहुत धन्यवाद और इस बहुत ही विशेष पैनल का हिस्सा बन कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी प्रस्तुति थोड़ी धीमी गति की होगी लेकिन मैं समय का पूरा ख्याल रखूंगी क्योंकि ज्यादातर बातें बोली जा चुकीं हैं। मैं माइकल, जो मेरे मित्र भी हैं, से सहमत हूँ और तीन पी (P) के बारे में, मैंने विदेश मामलों में कुछ लेख पढ़े थे, मेरे विचार से, जिसमें व्यक्तित्व को लेकर परेशानी आदि के बारे में भी बात की गई थी लेकिन तीन पी (P), इसकी व्याख्या अच्छी तरह से करते हैं। वास्तव में, यदि आप कुछ चीजों को देखें तो यहाँ कुछ उदाहरण हैं, मैंने सोचा, राजा, कि हमे देखना चाहिए कि ट्रंप के नेतृत्व ने पहले ही वर्ष में विश्व को क्या दिया है। एक तो यह है कि नाटो के सहयोगी देशों ने वास्तव में रक्षा खर्च में रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर सहमति जताई है।

दूसरी बात, हमारे सहयोगियों पर कम- से- कम तीन तरफ से अमेरिका ने सीधा हमला किया है और यह कुछ ऐसा था, मैंने सोचा और गाज़ा में शांति योजना है, संभव है यह बहुत कमज़ोर हो, हो सकता है कि शांति बोर्ड अभी भी काम कर रहा हो, लेकिन उनके पास एक योजना है। और बेशक ...

सी. राजा मोहन: विजया, क्या आप? कॉल करें। यह इंटरनेट है। महामारी के दिनों की ज़रूरतें।

के. पी. विजयालक्ष्मी: नमस्कार, क्या अब आप मुझे सुन सकते हैं?

सी. राजा मोहन: हमारा संपर्क कुछ देर के लिए, एक मिनट से, टूटा हुआ था।

के. पी. विजयालक्ष्मी: जी हाँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। शायद मैं भी वही करूँ जो माइकल ने किया था, अपना वीडियो हटा दूँ क्योंकि आजकल थोड़ी समस्या हो रही है। खैर, आपको जल्दी से बता दूँ कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यूरोप की सभ्यता के समाप्त होने की चेतावनी देती है। ये कुछ बातें हैं जिन्हें आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, उसकी पृष्ठभूमि के रूप में ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेकिन यदि आप इसे देखें, तो अभी भी बहुत सारा अधूरा काम चल रहा है। एक तो यह कि क्या वह वेनेज़ुएला की बागडोर अपने हाथों में लेने वाले हैं, यह एक समस्या है। विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

फिर यूक्रेन युद्ध का जारी रहना और उससे क्या नतीजा निकलेगा, चाहे वह अमेरिका की शांति की कोशिशें हों या पुतिन की प्रतिक्रियाएं, वगैरह। फिर ताइवान के चारों तरफ चीन की नौसेना, वायु सेना और मिसाइल बलों को इकट्ठा करना। एक बार फिर,

यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मुझे लगता है कि हमें विचार करना चाहिए। और हाँ, आप ईरान में बड़े पैमाने पर जारी विरोध प्रदर्शनों के भी साक्षी हैं। इसमें जेन ज़ी (Z) आदि भी शामिल हैं। तो बहुत सारा काम है। यदि आप दूसरे पी (P) को देखें जिसके बारे में व्यक्तित्व के हिसाब से बात की जा सकती है, तो उन्हें जीतने के लिए खेलना पसंद हैं, हर दिन जीतना। मुझे इस पर विश्वास है। लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में ट्रंप के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प विचार देता है।

दूसरा मुख्य मुद्दा जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, वह यह है कि क्या ट्रंप केवल राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन और जिनका नेतृत्व करते हैं, उतना भर ही है? या क्या कोई ट्रंपिज़्म भी है और ट्रंप डॉक्टर क्या है? मुझे लगता है कि ये तीन फ्रेमवर्क हैं जिनका प्रयोग कर हम समझ सकते हैं कि आगामी कुछ वर्ष कैसे होंगे, इसका सबसे अच्छा अंदाजा कैसे लगाया जाए। व्यापार के बारे में जो पहली बात मैंने नोटिस की, और दिनाकर इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिकी शक्ति का प्रयोग करने का संचालन तर्क बदल गया है क्योंकि अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य वास्तव में ज्यादा बदले नहीं हैं।

वे प्रधानता चाहते हैं, वे रोक लगाना चाहते हैं और फायदा उठाना भी चाहते हैं। यह संचालन तर्क है जो बदल गया है। फिर बोझ बांटना और सुरक्षा की गारंटी, क्या यह विश्वास की कमी है? क्या अब हम सहयोगी देशों आदि के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका पर विश्वास नहीं कर सकते? क्या यह केवल शर्तों के साथ बात को घुमा- फिराकर कहना है? तो हम रीफ्रेमिंग (नज़रिए में बदलाव) को कैसे समझें और अपने हितों को फिर से निर्धारित करने के लिए रिफ्रेमिंग का प्रबंध कैसे करें?

तीसरा है- तथाकथित नियम- आधारित व्यवस्था को खत्म करना। क्या यह सच है? या फिर क्या ऐसा है कि अब अमेरिकी रुख एक प्रकार की मूल्य बनाम हित की बहस से हट गया है और केवल हित की बात करता है वो भी अमेरिकी हित और सबसे पहले अमेरिकी हित? मैं बस इस बात का उल्लेख करना चाहती हूँ कि यह वैश्विक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका अभी भी व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली कारक है। लेकिन अब दूसरों के विश्वास में, उस शक्ति की उत्पादकता और संस्थागत एंकरिंग में कुछ कमज़ोरी आई है।

अब, इसका एक घरेलू पहलू भी है। माइकल ने बहुत संक्षेप में इसका ज़िक्र किया था। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जो संस्थागत नियमों को चुनौती देने को तैयार है, चाहे आप इसे तीसरे कार्यकाल का सवाल कहें या डेमोक्रेट्स के बीच मध्यावधि में क्या होगा, और यह चलता रहेगा। लेकिन संस्थागत नियम, क्या आप उसे विदेश नीत से जोड़ सकते हैं, या हमें कुछ अलग सोचना चाहिए? तो व्यवस्था से इसका क्या नतीजा निकलता है?

मेरे हिसाब से, तीन बातें हैं, और मैं यहीं खत्म करूँगा। पहली बात यह है कि इससे सभी ने बहुत ज्यादा पहले से ही बचाव- व्यवस्था शुरू कर दी है। यूरोपियन और भारत, एशियाई, हर कोई रणनीतिक स्वायत्तता और सुरक्षा संबंधों के विविधिकरण की बात कर रहा है। विश्व केवल बहुध्रुवीय नहीं हो रही है या अमेरिकी शक्ति के कमज़ोर होने की वजह से बहुध्रुवीय नहीं बन रही है बल्कि इसलिए भी क्योंकि अब देश वाशिंगटन से कुछ अस्थिरता की उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है। लेकिन इसे जो चीज़ चला रही है, वह विचारधारा है और यह केवल लेन- देन वाली लोकलुभावन राजनीति नहीं है, जैसा कि हमें यकीन दिलाया जाता है कि यह एक सौदा है। मुझे लगता है कि यह एक ज्यादा मज़बूत राष्ट्रवादी विश्वास प्रणाली है और यहीं पर हम सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प के सत्ता से हटने या पद छोड़ने के बाद ट्रम्पवाद कैसा दिखेगा।

तीसरे कार्यकाल के बारे में चौथा और आखिरी सवाल, मुदद् संवैधानिक बारीकियों से अधिक इसके नियमों, उनमें हो रही कमी और संस्थागत सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है जिसके बारे में हम सभी को सोचना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बाकी राज्य व्यवस्था से कुछ बहुत दिलचस्प व्यवहार सामने आ रहा है।

मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। लेकिन भारत और अमेरिका के बारे में, मैं सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम इस पर प्रश्नोत्तर सत्र में बात करेंगे। बहुत- बहुत धन्यवाद, राजा।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद, विजया। अब हम आखिरी स्पीकर की ओर बढ़ते हैं, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, पंखुड़ी, आपके पास 10 मिनट है।

पंखुड़ी गौर: मुझे उम्मीद है कि मैं प्रस्तुति यहीं से संचालित कर पाउंगी, है ना?

सी. राजा मोहन: पहले से कही बातों को मत दुहराएं। बस जरूरी बातें बताओ।

पंखुड़ी गौर: हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले, मैं इतने ज़रूरी विषय पर मुझे बुलाने के लिए आईसीडब्ल्यूए को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे साथी पैनलिस्ट ने सभी रणनीतिक, रक्षात्मक, सभी चीजों के बारे में बात की है। लेकिन मैं आर्थिक पहलू पर ध्यान देना चाहूँगी जिससे हम निपट रहे हैं, ट्रंप या टैरिफ 2.0 पर हम फोकस कर रहे हैं। तो, ज़ाहिर है, हम जानते हैं कि टैरिफ बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। यह उम्मीद है या अनुमान लगाया गया है कि व्यावसायिक व्यापार लगभग 5.5% से घटकर लगभग 8.5% हो सकता है। हम आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव देख रहे हैं, जहाँ चीन मैक्सिको और दक्षिण- पूर्व एशिया के ज़रिए अमेरिका को निर्यात कर रहा है।

हम देख रहे हैं कि इन ट्रंप टैरिफ की वैधता या टैरिफ में बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया है, और हम अभी भी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बेशक, फिर ग्रीनलैंड, ईरान, रूस के बारे में लगातार घोषणाएं हो रही हैं, फिर से 500% के लिए। ये सभी नई बातें हैं, या आप इन्हें क्या कहेंगे, यह उस पृष्ठभूमि का आधार है जिसे मैं आगे पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा और जहाँ भारत को लाभ हो रहा है और भविष्य के लिए भारत की क्या रणनीतियां होनी चाहिए।

टैरिफ बढ़ाने का मुख्य मकसद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाया गया राष्ट्रवादी तरीका है। उनके पास एकतरफा या आपसी टैरिफ नाम के बड़े टैरिफ हैं। अप्रैल, जुलाई से लेकर इस साल भी लगातार कई स्टेज आए हैं, वे इस पर फोकस कर रहे हैं, उन्होंने दो अलग- अलग देशों के लिए धमकी के रूप में या अपने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है, जो कि पिछली सरकार में ऐसा नहीं हुआ था।

ट्रम्प 1, हमने अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध देखे हैं। हमने 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ देखे हैं। हमने एनएएफटीए (NAFTA) में फिर से बातचीत देखी, फिर नया यूएसएमसीए (USMCA) आया। हमने चुनावी अभियान में इस तरह की धमकियाँ भी देखी हैं। बेशक, 2017 में वे टीपीपी से भी पीछे हट गए। राष्ट्रवादी विचारधारा तो पहले भी थी। इस विचार का समर्थन करने के लिए, उनके पास बहुत सारे घरेलू कानून हैं। हमारे पास आईएएपीए (IAAPA) है, हमारे पास खंड (सेक्शन) है, बेशक, आप सब जानते ही होंगें। इस बात को मैं यहीं छोड़ती हूँ और फिर इस बात पर ध्यान देती हूँ कि असल में, टैरिफ में इस वृद्धि का क्या औचित्य है?

तो अमेरिका का मुख्य ध्यान बढ़ते व्यापार घाटे पर है। यह सच है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका का व्यापार घाटा 2002 में 484 अरब डॉलर का था जो 2024 में बढ़कर 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह वह ग्राफ है जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि यह व्यापार घाटा हर साल 5% की दर से बढ़ रहा है। यह तीन गुना बढ़ चुका है। हम यह भी देख सकते हैं कि अमेरिका सबसे कम व्यापार पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहाँ व्यापारिक खुलापन यानी जीडीपी

के प्रतिशत के रूप में व्यापार, 2024 में अमेरिका के लिए केवल 25% के आस-पास है। जबकि मलेशिया जैसे देशों में यह लगभग 137% है। मेक्सिको में भी 75% है। दक्षिण अफ्रीका में 61% है और दूसरे देशों में भी।

तो व्यापार घाटा, स्पष्ट है, आपके सीएडी (CAD) को प्रभावित करता है। इसका आपके विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है। मूल रूप से, देश के आपके संसाधन पर जितना भी धन बाहर जाता है, व्यापार घाटा वहीं होता है। मूल रूप से, वे जिस व्यापार घाटा का सामना कर रहे हैं, उसके आधार पर टैरिफ बढ़ाना उनके लिए सही है। फिर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार घाटे में बड़े योगदान देने वाले को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि दो केंद्र सामने आ रहे हैं।

एक केंद्र में, हमारे पास चार बड़े देश हैं या आप कह सकते हैं चीन, जिसका कुल घाटे में योगदान 31% का है, उसके बाद मेक्सिको -23%, यूरोपीय संघ और कनाडा का स्थान है। फिर दूसरे देश भी हैं। वास्तव में ये शीर्ष 10 योगदानकर्ता देश हैं। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया और भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अमेरिका के व्यापार घाटे में योगदान कर रही हैं। यह 2024 में उनके कुल व्यापार घाटे का लगभग 3.7% है। लेकिन फिर जब आप इन देशों पर व्यापार घाटे के आधार पर लगाए गए टैरिफ को देखते हैं जो वे अमेरिका को दे रहे हैं, तो आपको अंतर भी नज़र आता है।

भारत की बात करें, जहाँ व्यापार घाटा 3.7% है, हम पर लगभग 50% टैरिफ लगाया जा रहा है। यूरोपीय संघ के मामले में यह लगभग 19.6% व्यापार टैरिफ है। हम केवल 15% हैं। और बाकी, हम इस ग्राफ़ के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरी बात यह भी है, यह मूल रूप से उन सभी देशों के लिए है जिन्हें मैंने मैच करने की कोशिश की है, लेकिन ग्राफ की सीमाओं को देखते हुए, लगभग 66% पर 15% का टैरिफ लगाया जा रहा है। मुझे लगता है कि बाकी पर 10% टैरिफ है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, कोई सहयोगी नहीं है और न ही कोई दुश्मन है। फिलीपींस पर भी टैक्स लग रहा है। यूरोपीय संघ पर भी टैक्स लग रहा है। भले ही फिलीपींस के साथ व्यापार घाटा यूरोपीय संघ के साथ होने वाले व्यापार लाभ से अलग है।

असल में हम किस चीज़ पर विचार कर रहे हैं? बढ़ते टैरिफ की वजह से, वे भी... तो ऐसा नहीं है कि किसी विशेष आयातक का लाभ मार्जिन 15% से 20% के आसपास हो, जहाँ टैरिफ में वृद्धि को कम किया जा सके, यानि लाभ मार्जिन को कम किया जा सके, और आप अमेरिका में माल बेच सकें। ऐसा नहीं है। लाभ मार्जिन केवल 5% के आसपास है, या शायद उससे भी कम और दूसरी बात, इसे लागू करने में भी चुनौतियाँ हैं। हालाँकि, उन्होंने कहा था कि वह 90 दिनों में 90 सौदा करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि निर्धारित समय- सीमा में केवल एक ही डील हो पाई। निश्चित रूप से ऐसे हालात में डब्ल्यूटीओ के तहत एमएनएफ (MNF) टैरिफ का चलन बहुत ज़रूरी है।

अब, जब हम विशेष रूप से भारत की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका और भारत का महत्व, सबसे बड़ा व्यापार निर्यातक, निश्चित रूप से, शीर्ष 10 निर्यातकों में से एक है। वर्ष 2017 से 2024 तक भारत का अमेरिका को निर्यात सालाना 8.1% की दर से बढ़ा है। इसी तरह हमारा व्यापार अधिशेष भी बढ़ रहा है। तो निर्यात, आयात, इन दोनों के बीच का अंतर आपका व्यापार घाटा है। वर्ष 2024 में, यह लगभग 40 अरब डॉलर था, जहाँ भारत अभी है। इसमें विशेष रूप से 2009 से 2013, और 2019 से 2021 के बीच तेज़ी से वृद्धि हुई है।

अब, भारत के पास जो व्यापार अधिशेष है, उस पर जब हम ध्यान देते हैं तो यह व्यापार के 21 व्यापक क्षेत्रों में से ही है। 18 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भारत का व्यापार अधिशेष है। केवल तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत का व्यापार घाटा है। लाल रंग वाले व्यापार घाटे को दिखा रहे हैं जो भारत का है, जबकि हरे रंग वाले अमेरिका के व्यापार अधिशेष बनाम भारत के व्यापार अधिशेष को दिखा रहे हैं। यह केवल बड़े क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। आप इसे अध्याय स्तर पर देख सकते हैं। किसी भी अलग- अलग स्तर पर, हम तकनीक, प्रौद्योगिकी- युक्त वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं।

जब हम तकनीक वाले उत्पादों की बात करते हैं, केवल प्राथमिक क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ अमेरिका का व्यापार घाटा है। बाकी, जब हम सरल प्रौद्योगिकी, मध्यम, उच्च, हर जगह की बात करते हैं तो भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है। इसी तरह, एंड- यूज़र स्तर पर भी। केवल प्राथमिक क्षेत्र में। बाकी अर्ध- निर्मित, पुर्जों और घटकों, पूंजीगत वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुएं, हर जगह भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है। हालांकि, जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो यह कहता है कि विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अधिक विनिर्माण वस्तुओं का निर्यात करते हैं। विकासशील देश प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात अधिक करते हैं।

तो, मैं अब बस दो मिनट का समय लूंगी। मैंने मूल रूप से यह करने का प्रयास किया है कि महीने के हिसाब से, मैंने यह देखना का प्रयास किया है कि सभी क्षेत्रों में हम अमेरिका को क्या निर्यात कर रहे हैं और टैरिफ की वजह से इसमें क्या बदलाव आया है। जब आप हरे बुलबुले देखते हैं, तो यह, जैसा कि 85 नंबर चैप्टर का नंबर है। यह 2005 से 2024 तक भारतीय निर्यात का चैप्टर- स्तर का विश्लेषण है। मूल रूप से, जुलाई 2005 और जुलाई 2024। वृद्धि क्या है? हरे वाले वृद्धि को दर्शा रहे हैं और लाल बुलबुले उस विशेष क्षेत्र में कमी को दर्शा रहे हैं। तो जुलाई में आपके पास 28 निगेटिव थे, जो अगस्त में बढ़ कर 54 निगेटिव हो गए और सितंबर में 79। धीरे- धीरे हम देख रहे हैं कि चैप्टर- स्तर पर भी, पिछले साल के उसी महीने की तुलना में, कई क्षेत्रों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है।

भारत के पास मूल रूप से दो विकल्प हैं। एक है सुलह, जहाँ हम मिशन 500 पर ध्यान दे रहे हैं। हम 2030 तक दो तरफा व्यापार के तौर पर 500 बिलियन डॉलर के सौदे का लक्ष्य रख रहे हैं, और जहाँ अमेरिका को भारत में खाए जाने वाले फल, मेवे जैसे बादाम, सोयाबीन, पेय पदार्थ और स्पिरिट्स (शराब) और बेशक खनन क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में बाज़ार तक पहुँच मिलेगी। भारत-अमेरिका समझौते के साथ भी, हम व्यापार और तकनीक में सहयोग की बात कर रहे हैं। एक आरएआई अध्ययन है जिसने कहा है कि यदि यह सफल होता है, जैसा कि यह प्रक्रियाधीन है, लेकिन अनुमान है कि मिशन 500 के बाद, भारत का निर्यात लगभग 20%, आयात लगभग 28% और व्यापार संतुलन बीच में घटकर लगभग 25 अरब डॉलर हो जाएगा। निश्चित रूप से, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अंतर- क्षेत्रीय व्यापार होता है। हम भारत और अमेरिका दोनों पर फोकस कर सकते हैं।

दूसरा तरीका है जवाबी कार्रवाई करना यानी उन क्षेत्र में जहाँ अमेरिका को इन सभी क्षेत्र में लाभ है जैसे कृषि, तो फल और मेवे, खनिज। तो भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन बेशक, हम अभी व्यापार के विविधिकरण पर ध्यान दे रहे हैं। हम अलग-अलग क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से काम कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ही हैं। बेशक, हम ईएफटीए, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों के साथ नए व्यापार एफटीए पर काम कर रहे हैं। हम न्यूज़ीलैंड और यूरोपीय संघ पर आते हैं, यह सबसे बड़ा सौदा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम अंतर- ग्लोबल साउथ पर काम कर रहे हैं जो केंद्रित है। यही कुछ मुख्य बातें थीं जिन पर मैं अपने विचार साझा करना चाहती थी। धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद, पंखुडी। आपका बहुत- बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे पैनल के चारों सदस्यों ने काफी कुछ कवर कर लिया है। हमारे पास चर्चा के लिए लगभग 40 मिनटों का समय है। मैं यह करूँगा कि एक बार में तीन सवाल लूंगा और फिर पैनल के सदस्यों से उनके जवाब देने को कहूँगा। और हाँ, हमारे दोनों ऑनलाइन पैनलिस्ट ने अपना बहुत समय दिया है तो यदि आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल पूछने से पहले स्पष्ट कर दें। सवालों को संक्षिप्त और सरल रखें ताकि अधिक- से- अधिक लोग चर्चा में हिस्सा ले सकें। सर, क्या आप कमान संभालना चाहेंगे? तो अब, डॉ. राजदूत सज्जनहार।

अशोक सज्जनहार: जी हाँ, बहुत- बहुत धन्यवाद, राजा और पैनल के सभी सदस्यों को भी बहुत- बहुत धन्यवाद क्योंकि आप सभी ने बहुत ही संक्षिप्त और केंद्रित प्रस्तुति दी है आज। तो मेरे दो सवाल है। पहला सवाल माइकल कुगेलमैन से है। माइकल, चूंकि

आप शायद अभी वहाँ नहीं हैं लेकिन आप वाशिंगटन, डीसी में रहते हैं, आप अमेरिका में हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि अमेरिकी हलकों में भारत के लिए किस प्रकार का समर्थन है? क्योंकि पहले ऐसा सोचा जाता था कि चाहे कांग्रेस हो, हमारे पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, सीनेट में, व्यापारियों के बीच और लोगों से लोगों के संपर्क यानी पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट में सबसे अधिक, सबसे बड़ा समूह है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका से बहुत सारी दुश्मनी वाली और विरोधी बातें कही जा रही हैं। अलग- अलग स्तर पर, व्यापार आदि में आपको वहाँ किस प्रकार का समर्थन दिख रहा है?

मेरा दूसरा सवाल दिनाकर से है, क्या आपको श्रीमान ट्रंप के खिलाफ किसी प्रकार का विरोध नज़र आता है, उन सभी नीतियों के लिए जो वह बीते एक साल से अपना रहे हैं, चाहे वे देश के भीतर हो, कांग्रेस से, न्यायालय से, हमने कुछ देखा है। लेकिन इसका असल में अधिक असर नहीं हुआ है। वैश्विक स्तर पर भी, जी20(G20) के मामले में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के साथ जो किया, उन्हें वहाँ से निकाल दिया, और बाकी जो भी गड़बड़ियां हमने उनसे होते हुए देखी हैं। क्या आपको वैश्विक और घरेलू स्तर पर, क्योंकि मुझे यकीन है कि बहुत अधिक नाराज़गी है, लेकिन क्या इसका नतीजा उनके खिलाफ किसी प्रकार के विरोध के रूप में सामने आ रहा है?

सी. राजा मोहन: धन्यवाद, मुझे लगता है कि अमेरिका में घरेलू स्तर पर समर्थन का स्तर और विरोध की संभावना। डॉ. उमा, क्या आप कुछ पूछना चाहती हीं?

उमा: सबसे पहले, मैं सभी वक्ताओं को शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे लगता है कि हम सभी ने हर एक प्रस्तुति से बहुत कुछ सीखा है। मैं बस यह जानना चाह रही थी कि हर कोई इस मौलिक बदलाव के बारे में बात कर रहा है जो अमेरिका की घरेलू राजनीति में हो रहा है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती थी कि इस घरेलू असंतोष और उसके बाद प्रशासन के व्यवहार के स्रोत क्या हैं? मेरे कहने का मतलब है, यह कहना तो ठीक है कि घरेलू राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है लेकिन इस घरेलू असंतोष की असली वजह क्या है?

सी. राजा मोहन: अच्छी बात है, इसका जवाब आप दीजिएगा। कृपया अपना परिचय दें।

राहुल त्रिपाठी: जी हाँ, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है। मैं गोवा विश्वविद्यालय से हूँ। बहुत ही संक्षेप में, मेरा सवाल माइकल और प्रो. राजा मोहन से है। उन्होंने जो कुछ भी देखा और किया उसके आधार पर वे दक्षिण एशिया क्षेत्र को किस तरह से देखते हैं? यदि आप इस बारे में कुछ बता सकें।

सी. राजा मोहन: अच्छी बात है। मैं माइकल से शुरू करना चाहूँगा। माइकल, मुझे लगता है कि इस समय आप वास्तव में विश्व के दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो क्या आप शुरू करना चाहेंगे?

माइकल कुगेलमैन: ज़रूर। तारीफ़ का शुक्रिया। पहला सवाल भारत और अमेरिका सर्कल में समर्थन का स्तर के बारे में था, मैं कहना चाहूँगा कि ह्वाइट हाउस से जो भावना आ रही है, वह असल में थोड़ी अजीब है। मेरा मानना है कि पूरे आधिकारिक वाशिंगटन में, नीति निर्माताओं, कैपिटल हिल, विश्लेषण करने वाले समुदाय, विचार मंचों, इन सभी में, भारत के साथ साझेदारी को लेकर अभी भी बहुत समर्थन है, अमेरिका- भारत संबंधों की दिशा को लेकर चिंता और एक तरह की घबराहट भी है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, ह्वाइट हाउस ही विदेश नीति या भारत के प्रति नीति चला रहा है। इसलिए भारत के साथ संबंधों में समस्या है क्योंकि जो लोग अब साझेदारी बनाए रखने में सबसे कम दिलचस्पी रखते हैं, वे ही भारत के प्रति नीति को नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन यदि आप मध्यम- स्तर वाले अधिकारियों, सरकारी विभाग बीओडी (BOD) के नौकरशाहों, अंतरएजेंसी समुदाय

के लोगों से बात करें, तो मेरे अनुभव में और मैं दूसरों को भी जानता हूँ, ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जो भारत के प्रति नीति पर ह्वाइट हाउस जो कर रहा है, उससे सहमत हों।

कैपिटल हिल को देखते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी संकेतों में बताया था, मैं यह कहूँगा कि सभी जगहों पर, जिसमें ह्वाइट हाउस और सीनेट, दोनों में, रिपब्लिकन भी हैं, भारत के साथ साझेदारी की लगातार दृढ़ इच्छा है, लेकिन वे चिंतित हैं, मैं कहूँगा कि डरे हुए भी हैं कि ह्वाइट हाउस की भारत के प्रति नीति की दिशा को लेकर अपनी नाराज़गी को खुलकर ज़ाहिर करें। यह सच है, जैसा कि सवाल पूछने वाले ने कहा, हमें ट्रंप के कुछ समर्थकों की तरफ से कुछ बहुत ही बुरी बातें, सीधे तौर पर नस्लवादी भावनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन मैं इसे अधिक बढ़ा- चढ़ा कर नहीं बताना चाहूँगा।

मैं यह कहूंगा कि एमएजीए (MAGA) बेस में ऐसे सदस्य हैं जो भारत के बहुत समर्थक हैं और भारत या भारतीय- अमेरिकियों या जो भी मामला हो, उसकी बिल्कुल भी आलोचना नहीं करते लेकिन दुर्भाग्य से MAGA बेस में ऐसे भी आलोचक हैं जो भारत की बहुत अधिक आलोचना करते रहे हैं और इससे निश्चित रूप से संबंधों को कोई लाभ नहीं होता। आपके सवाल के जवाब में मैं यह कहूँगा कि वाशिंगटन में व्यापक माहौल, जब बात आती है कि भारत को किस नज़रिए से देखा जाता है, और साझेदारी के लक्ष्य क्या हैं, तो यह काफी हद तक वैसा ही है जैसा बीते कुछ दशकों से रहा है, जब केवल ह्वाइट हाउस ही एक अपवाद रहा है।

फिर आखिरी सवाल के लिए, मुझे लगता है कि दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया, मुझे नहीं पता कि उसका मतलब यह था कि ट्रंप दक्षिण एशिया को किस तरह देखते हैं या मैं इसे कैसे देखता हूँ। जहाँ तक ट्रंप की बात है, वह इस मामले पर बिल्कुल विचार नहीं करते। वे दुनिया को उस नज़रिए से नहीं देखते। जहाँ तक दक्षिण एशिया की बात है, वे इसे अमेरिका के आर्थिक हितों और व्यापारिक हितों के नज़रिए से देखते हैं। यही वजह है कि आठ दक्षिण एशियाई देशों में से चार देशों- भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश पर टैरिफ लगाए गए हैं। मुझे लगता है कि यदि वे इस क्षेत्र को व्यापार के नज़रिए से देखते हैं तो इसे भू-राजनीतिक मुकाबले के नज़रिए से नहीं देखते, कम- से- कम इस समय तो नहीं देख रहे।

बहुत ही संक्षेप में, यदि मैं दक्षिण एशिया को देखने के अपने नज़रिए की बात करूँ तो बेहतर होगा कि मैं यह बात किसी और दिन के लिए रहने दूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पिछली सरकार में हिंद- प्रशांत के बड़े दायरे में रखा गया था। ट्रंप सरकार हिंद- प्रशांत शब्द का प्रयोग अधिक नहीं करती, जिससे फिर से वही बातें सामने आती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप दक्षिण एशिया को उस नज़रिए से नहीं देखते। वे इस क्षेत्र को व्यावसायिक लेन- देन के नज़रिए से देखते हैं जो व्यापार और टैरिफ नीतियों के इर्द- गिर्द घूमता है। धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: ठीक है। दिनाकर, क्या आप पुशबैक पर बात करना चाहेंगे?

दिनाकर पेरी: बीते दो दिनों में एक संकेत यह है कि अमेरिकी शेयर बाज़ार में जबरदस्त गिरावट आई है और डॉलर असर में करेंसी बास्केट से लगभग 1% गिर गया है। यदि यह एक संकेत है तो बस यह सब छोड़ दें। क्या होता है कि...

सी. राजा मोहन: आर्थिक और वित्तीय...

दिनाकर पेरी: जी हाँ। इसका असल में प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आखिरकार क्या होता है कि यदि आप ट्विटर चैट या उदाहरण के लिए एक्स (X) पर देखें तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन वह ज़मीन पर आम अमेरिकियों की अभिव्यक्तियों में

नहीं बदलेगा। ऐसा तभी होगा जब आर्थिक हालात सच में खराब होंगे और इसमें कुछ चक्र, कुछ तिमाहियों का समय लगता है। बीते कुछ दिनों में बॉन्ड मार्केट भी गिरा है लेकिन रुझान कैसा है यह हमें नहीं पता। एक, यह उसके व्यापार वाला हिस्सा है।

भू- राजनीतिक नज़रिए से, जैसे, इज़रायल ने आज कहा कि वे शांति बोर्ड का समर्थन करेंगे लेकिन फिर नॉर्वे ने कहा कि हम इससे दूर रहेंगे। फ्रांस भी उसी दायरे में है। शायद शांति बोर्ड और ग्रीनलैंड एक प्रकार से माहौल को बदलने के लिए परिवर्तन बिन्दु हो सकता है। ऐसा लगता है क्योंकि वास्तव में यह संकट अब यूरोप के लिए कई प्रकार से घर तक पहुँच गया है।

सी. राजा मोहन: विजया, क्या आप घरेलू असंतोष के स्रोत पर संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगी? क्या आप कनेक्टेड हैं? अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप घरेलू असंतोष, इसके स्रोत पर कुछ कहें।

के. पी. विजयालक्ष्मी: अच्छी बात है। बहुत- बहुत धन्यवाद। और श्रुति, मैं आज की व्यवस्था के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। यह शानदार विचार है। तो, दो बातें हैं जिसे मैंने नोटिस किया- पहली बात, जब ट्रंप चुने गए, हम जनता का ध्यान देख रहे थे, कम- से- कम, कमोबेश उन कम आय वाले परिवारों के समर्थन पर जो इससे प्रभावित हुए थे...

सी. राजा मोहन: अच्छी बात है, जब तक विजया से फिर से संपर्क स्थापित हो पाता है, मैं यह कहना चाहूँगा कि, देखिए, समस्या यह है कि हमने अमेरिका के घरेलू राजनीति पर ध्यान नहीं दिया है। हमने इसे हमेशा समग्रता में देखा है। और हममें से ज्यादातर लोग इसे विदेश नीति या व्यापार के मामले में अमेरिका के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय आधार पर देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीते 20 सालों में जो हुआ है, विजया, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें, फिर आपके पास आता हूँ मैं, वह यह है कि व्यापार को लेकर नज़रिए में वास्तव में बदलाव आया है। क्योंकि लोगों के एक बड़े हिस्से को वैश्वीकरण से लाभ नहीं मिला है। जैसा कि होता है, मेरे कहने का मतलब है, वे शायद सबसे अधिक संख्या में न हों, लेकिन मध्यपश्चिम में उन्होंने जिस प्रकार से मतदान किया है, उसका प्रभाव चुनावी नतीजों पर पड़ा है। यह अमेरिकी गोरे श्रमिक वर्ग का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे लगा कि वैश्वीकरण ने उन्हें प्रभावित नहीं किया है।

दूसरा, मुझे लगता है कि आव्रजन का मुद्दा, मेरे कहने का अर्थ है, यदि आप अपने बीच कम समय में बाहर के लोगों की बढ़ती संख्या देखते हैं, जिसमें भूरे, काले, सब तरह के लोग हैं तो मुझे लगता है कि इससे प्रतिक्रिया होना तय है। जैसे हमारी सरकार विदेशियों, बाहरी लोगों की बात करती है, अमेरिका, जो खुद अप्रवासियों का समाज है, वह आव्रजन को लेकर बहुत कम चिंतित लगता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप इतिहास को देखें तो अमेरिका के इतिहास में आव्रजनविरोधी भावना की कई लहरें आई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम एक और दौर से गुज़र रहे हैं।

गठबंधन के बारे में, फिर से, गठबंधन के प्रति रवैया, यदि आप हमारे उदार मित्रों से भी पूछें जो चुनाव करवा रहे हैं तो अमेरिकी जनता अभी भी गठबंधन का समर्थन करती है। लेकिन सच यह है कि एक बड़ा वर्ग सोचता है कि सहयोगी मुफ्त में लाभ उठा रहे हैं, अमेरिका को युद्धों में घसीटा जा रहा है, हमें ये नहीं रखने चाहिए। ये घरेलू तर्क है जो विदेश नीति में सामने आते हैं और मैं कहूँगा कि यही असली बदलाव हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ राजनीति हालात के हिसाब से ढल जाती है। मुझे लगता है कि हमने ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी विदेश नीति को एक बड़ी योजना के रूप में लिया है जिसका उसकी घरेलू राजनीति से कोई लेना- देना नहीं है। लेकिन आज मुझे लगता है कि घरेलू राजनीति अधिक प्रभावकारी है। विजया, क्या आप जल्दी से अपनी बात पूरी करना चाहेंगी?

के. पी. विजयालक्ष्मी: जी हाँ, मैं यह कह रही थी कि यदि अमेरिका का आर्थिक भविष्य मुख्य रूप से राष्ट्रपति को इन उच्च-तकनीक वाले उद्योगों के समर्थन से तय होता है, तो रस्ट बेल्ट को इससे बहुत कम लाभ होगा। लेकिन फिर भी हम यह गठबंधन

देख रहे हैं और यही इस राष्ट्रपति की शक्ति का असली स्रोत है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा बदलाव है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि यदि आप इसे देखें, तो मेडिकेड (चिकित्सीय सहायता), खाद्य सहायता प्रोग्राम आदि पर खर्च में कटौती और उन्होंने बड़े खूबसूरत बिल के बारे में जो कहा, मेडिकेड प्रोग्राम में कटौती से ग्रामीण इलाकों के उन लोगों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि वैश्वीकरण को लेकर गुस्सा था।

फिर भी वे ट्रंप के समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा हैं और हमें इस स्रोत को लोकप्रिय राजनीति के बहुत ही आवश्यक वैचारिक सिद्धांतों के रूप में समझने की आवश्यकता है, जिसके बिना मतदाता जनसांख्यिकी बहुत अलग दिखेगी। फिर दूसरी ज़रूरी बात यह है कि विदेश से आने वाले सस्ते श्रमिकों के लिए ट्रंप प्रशासन का जवाबी- प्रस्ताव (काउंटर ऑफर)। मुझे लगता है कि केवल आव्रजन और ब्राउन फेज़ से अधिक यदि आप इसे डिकोड करें तो मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन यह सस्ता श्रम है, हमें फंसाया जा रहा है क्योंकि हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, उन्हें बहुत कम वेतन पर नौकरियाँ मिल रही हैं।

तो इस प्रकार के लेन-देन, यदि आप चाहें तो, इस राष्ट्रवाद या अमेरिका प्रथम के लिए राष्ट्रवादी समर्थन है, जो मुझे एक नई धार्मिकता या अमेरिकी जीवन के उद्देश्य, अमेरिकी सपने वगैरह को गढ़ने जैसा लगता है। मुझे लगता है कि यह एक बात है। इसके गहन परिणाम यह हैं कि अमेरिका प्रथम नीति न केवल किसी दूसरे देश के साथ बल्कि परंपरागत सहयोगियों के साथ भी अपने संबंध बदल देगी। इसलिए, हमें स्रोत को देखना होगा, फिर, मैं घरेलू राजनीति को आकार देने वाली मतदाता रही हूँ और प्रमाण इतने स्पष्ट हैं कि घरेलू राजनीति अक्सर दखल देती है और वास्तव में विदेश नीति के फैसलों को घरेलू राजनीति और गठबंधन की वजह से, यहाँ तक कि अप्रिय, आर्थिक रूप से अव्यवहारिक निर्णयों को भी समझाती है।

इसलिए, क्या ट्रम्पवाद ट्रम्प के बाद भी रहेगा? जी हाँ। ऐसा हो सकता है क्योंकि यह देश के भीतर गठबंधनों पर निर्भर करता है। बहुत- बहुत धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद, विजया। अगला सवाल, कोई और पूछना चाहता है? जी हाँ, ठीक पीछे, जी हाँ आप। मेहता, सर।

मेहता: क्या माइकल अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं?

सी. राजा मोहन: जी हाँ, मेरे ख्याल से तो जुड़े हैं।

मेहता: जी पूछिए। माइकल, मेरा सवाल आपसे है- आप चौथा पी (P) यानी लाभ को भूल गए। ट्रंप ने घमंड और तारीफॉ के अलावा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इनमें से कई एजेंडा को बहुत स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाया है। धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: अच्छी बात है, कोई और? जी हाँ, वहाँ वह महिला। आप खड़ी क्यों नहीं हो जातीं?

स्तुति गोगोई: जानकारी के लिए धन्यवाद। मेरा नाम स्तुति गोगोई है। मैं परिषद में शोध इंटर्न हूँ। मैं ईरान में बदलती स्थिति के लिहाज़ से ट्रंप 2.0 को समझना चाहती थी। हम बहुत समय से ईरान में संभावित सत्ता परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या अब यह होने वाला है, अमेरिका और ट्रंप प्रशासन के साथ ईरान में सत्ता परिवर्तन?

सी. राजा मोहन: तो आप यहाँ किसी को चाहते थे? जी हाँ, कृपया। हाँ, ये सामने।

आदित्य: नमस्कार, मैं आदित्य हूँ, SIH ANU में अमेरिकी अध्ययन से पीएचडी स्कॉलर हूँ। मेरा भारत- अमेरिका संबंधों पर एक सवाल है, ट्रंप के एक वर्ष में भारत ने विशेष रूप पर क्या हासिल किया है? क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी चीजों के बारे में देखते हैं, तो भारत इनमें से ज्यादातर मुद्दों पर चुप क्यों रहा, जबकि ट्रंप इन मुद्दों पर हर समय बोलते नज़र आते हैं। भारत को कम- से- कम एक साल में इन सब बातों का हल कैसे निकालना चाहिए?

सी. राजा मोहन: कभी- कभी खामोश रह जाना बेहतर विकल्प होता है। मैं अभी माइकल का रुख करता हूँ। माइकल, मैं अगले सवाल पर वापस आऊँगा। माइकल, मुझे हैरानी हो रही है कि किसी ने आपसे पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछा। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप दक्षिण एशिया के प्रति अमेरिकी नीति की बात की, यदि आप 2017 में वापस जाएं, तो दक्षिण एशिया पर एक नीति हुआ करती थी, जिसकी घोषणा ट्रंप ने नवंबर, 2017 में की थी, यदि मुझे ठीक से याद है। वह वास्तव में बहुत भारत- प्रथम, पाकिस्तान- विरोधी प्रकार की नीति थी। आज पाकिस्तान पर फोकस के साथ यह बदलाव क्यों हुआ है? बेशक, हम भारतीय, जब भी पाकिस्तान का ज़िक्र होता है, तो हम पागल हो जाते हैं कि जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर को लंच करने के लिए बुलाया गया है। वहाँ क्या बदला है?

मुझे लगता है कि कई भारतीय सोच में पड़ गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान आज अमेरिका को वास्तव में ऐसा क्या दे रहा है या ट्रंप के लिए पाकिस्तान आज इतना ज़रूरी क्यों है? क्या यह मिडिल ईस्ट है? क्या क्रिप्टो है? क्या यह संसाधन हैं? तो शायद आप इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और लाभ के उद्देश्य, ईरान, भारत- अमेरिका संबंधों के भविष्य पर सामने आए दूसरे मुद्दों पर भी विचार कर सकते हैं।

माइकल कुगेलमैन: हाँ, जरूर। धन्यवाद राजा। वास्तव में, मैं आपको पाकिस्तान से संबंधित सवाल का जवाब चौथे पी (P) यानी प्रॉफिट (लाभ) के मुद्दे पर पहले सवाल को भी बताकर शुरू कर सकता हूँ। मैंने अपने पहले पी (P) में पहले ही कहा था कि ट्रंप प्रशासन विदेश नीति के लिए बहुत सख्त व्यावसायिक नज़रिया अपनाता है और मेरा मानना है कि इससे पाकिस्तान को फायदा हुआ है। पाकिस्तान इस प्रशासन के सामने खुद को एक उपयोगी साझीदार के रूप में प्रस्तुत करने में बहुत असरदार रहा है जब बात अमेरिका को विदेशों में व्यावसायिक मौकों का लाभ उठाने में मदद करने की आती है, आम तौर पर, केवल पाकिस्तान में ही नहीं।

हम सब जानते हैं कि कई सालों से, कई दशकों से, पाकिस्तानी अधिकारी अपने महत्वपूर्ण खनिज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कई वजहों से उन्हें अधिक खरीददार नहीं मिले, जिन्हें हम आसनी से पहचान सकते हैं। लेकिन स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति महत्वपूर्ण खनिजों पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। हम उन खनिजों तक पहुँच चाहते हैं और ऐसा लगता है कि यदि उन्हें प्राप्त करने में कोई परेशानी आती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि पाकिस्तान में ज़रूर होगा, यह देखते हुए कि वे कहाँ मौजूद हैं।

मुझे लगता है कि राजा, आपके सवाल का जवाब देने का यह एक तरीका है कि पाकिस्तान महत्वपूर्ण खनिजों पर एक उपयोगी साझीदार के रूप में खुद को पेश करके प्रशासन का ध्यान खींचने में कामयाब रहा है, लेकिन एक और बात भी है जो वैश्विक स्तर पर इस प्रशासन के लिए बहुत दिलचस्प है, वह है- क्रिप्टो। पाकिस्तान का, ज़ाहिर है, क्रिप्टो से कोई लेना- देना नहीं था, जब तक कि, शायद यह कोई इत्तेफ़ाक नहीं था, ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, जब नई क्रिप्टो काउंसिल की घोषणा की गई। पाकिस्तान में अभी भी क्रिप्टो को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, और फिर भी हम पाकिस्तान और ट्रंप के परिवार के सदस्यों के बीच क्रिप्टो पर समझौता देख रहे हैं। यह एक वजह है।

मुझे लगता है कि... यही मुख्य कारण है कि हमने अमेरिका- पाकिस्तान संबंधों में यह फिर से मज़बूती देखी है। लेकिन इसके और भी कारण है। मुझे लगता है कि भू- राजनितिक स्थितियों को देखते हुए, मध्य पूर्व में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए, ह्वाइट हाउस ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण माना है क्योंकि यह मध्यपूर्व के करीब है, क्योंकि इसके जीसीसी देशों के साथ करीबी साझीदार हैं, वगैरह। मुझे लगता है कि यह भी एक कारण है।

मुझे लगता है, और मैं जानता हूँ कि यह बात भारत में अच्छी नहीं लगेगी लेकिन मैं यह कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ, उसने ट्रंप प्रशासन का ध्यान खींचा, जिसमें कई भारतीय विमानों को भी मार गिराया गया था। मेरे विचार में यह पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई बैठकों में यह बात ज़रूर उठाई होगी, और सच कहूँ तो शायद इससे राष्ट्रपति ट्रंप प्रभावित हुए होंगे।

व्यक्तित्व के मुद्दे पर आते हैं, मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने जैसे नेताओं या उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उनके जैसा बनना चाहते हैं। उन्हें सत्ता और शक्ति पसंद है। उन्हें ताकतवार लोग पसंद हैं। आमिर के मामले में जो हुआ, यह सब उसी के बारे में है। मुझे लगता है कि इससे यह पता चलता है कि हमें मुनीर पर ट्रंप का इतना अधिक सकारात्मक रवैया क्यों दिख रहा है। आखिरी बात और यह बहुत समय से सबके सामने है, पाकिस्तान ने वाशिंगटन में कुछ असरदार पैरवीकार तैयार किए हैं जिससे पाकिस्तान को ट्रंप तक पहुँचने में मदद मिली है और शायद इसी वजह से उसे प्रशासन से कुछ ऐसे संदेश और बातें सुनने में मदद मिली है जो पाकिस्तान सुनना चाहता है।

दूसरे मुद्दों पर, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई स्पष्ट सूची नहीं है लेकिन शायद हमें यहाँ थोड़ी हलचल की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपने पहले इसका जिक्र किया था, रोजर, ट्रंप कभी- कभी अमेरिका के दुश्मनों के प्रति अमेरिका के साझीदार से अधिक दोस्ताना लगते हैं। ईरान एक अपवाद है। ट्रंप का अतीत में रूस, चीन यहाँ तक कि उत्तर कोरिया से भी, ऐसा लगता है कि विशेष लगाव रहा है। हमेशा से वे ईरान के प्रति बहुत अधिक शत्रुतापूर्ण रवैया रखते आए हैं। मैं ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाईयों या किसी भी प्रकार की अमेरिकी कोशिशों की संभावनाओं के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करने वाला लेकिन मुझे लगता है कि यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ट्रंप ने कभी भी ईरान और विशेष रूप से वहाँ की सरकार के प्रति सुलह वाला रवैया नहीं अपनाया है।

भारत अमेरिका संबंधों के सवाल पर आखिरी बात, एक साल बाद भारत ने क्या हासिल किया है, मुझे लगता है कि यह एक बात बताना ज़रूरी है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। भले ही अभी रिश्ते कितने भी खराब क्यों न हों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बीते एक साल में सहयोग जारी रहा है। अमेरिका और भारत ने बीते एक साल में एक संयुक्त उपग्रह लॉन्च किया था। सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। अमेरिका में एफबीआई भारत के साथ मिलकर कई ऐसे लोगों को पकड़ने में सहयोग कर रही है जिन्हें भारत आतंकवादी या फिलिस्तीनी मानता है।

मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि संकट को लेकर इतने शोर- शराबे के बावजूद, चीजें हुई हैं और इसलिए इस लिहाज़ से भारत के नज़रिए से कुछ उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं, कि उनके हितों की रक्षा हुई है और वह कई महत्वपूर्ण पहलों पर अमेरिका के साथ सहयोग कर पाया है। धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद। हमारे पास पांचवां पी (P), पे टू प्ले (pay to play) है। वाशिंगटन में लामबंदी इसी तरह काम करती है। पंखुड़ी, क्या आप लाभ के मुद्दे पर संक्षेप में कुछ कहना चाहती हैं? जब आपने व्यापार मुद्दों के बारे में बात की, इससे कितना फ़र्क पड़ता है?

पंखुड़ी गौर: मूल रूप से, जैसा कि मैंने अपने प्रस्तुति में लाभ मार्जिन के बारे में बात की थी। जब हम बात कर रहे हैं, या असल में, ऐसा नहीं है कि किसी खास देश पर 50% टैरिफ या किसी देश विशेष पर कुल मिलाकर 10% टैरिफ लगाया जाए। इसलिए अलग- अलग आयातकों का इसके लिए लाभ का मार्जिन अलग- अलग होता है। उनके लिए इसे ध्यान में रखना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा, बेशक, ऐसे अनुमान भी लगाए गए हैं कि अभी, सभी भारतीय आयातकों और भारतीय निर्यातकों के लिए, जो टैरिफ लगाया गया है, वह ....

सी. राजा मोहन: यहाँ हम एक व्यक्ति के रूप में लाभ की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलह है, मेरे विचार से आपको यह दिखाना होगा, यही वह संदर्भ है जिसमें...

पंखुड़ी गौर: बिल्कुल ठीक। स्पष्ट है, मैं यहाँ परंपरागत या व्यापार के नज़रिए से बात नहीं कर रही हूँ लेकिन जब यूरोपीय संघ व्यापार बज़ूका प्रयोग करने और अमेरिका की सर्विसेज औऱ विशेष रूप से अमेजन, नेटफ्लिक्स और मेटा जैसी कंपनियों को प्रभावित करने की धमकी देता है, तो ज़ाहिर है, इसका उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और फिर, ज़ाहिर है, इससे ग्रीनलैंड के बारे में उनका नज़रिया बदल सकता है।

सी. राजा मोहन: क्या आपको लगता है कि हमें चुप रहना चाहिए या फिर से पहले जैसा ही रवैया अपनाना चाहिए...

दिनाकर पेरी: नहीं, नहीं। चुप रहना अपने हक में है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। चाहे वह सैन्य निर्माण हो या राजनयिक मामले, कभी- कभी आपको अलग तरह से काम करना पड़ता है और यह असल में कूटनीति में काम करता है। पाकिस्तान पर एक बहुत ज़रूरी बात, इसमें ईरान का एंगल भी है और अफगानिस्तान का भी। बगराम को फिर से खोलने में अमेरिका की दिलचस्पी, पाकिस्तान बन जाता है.... हम जानते हैं कि यह कितना ज़रूरी है। साथ ही ईरान की स्वयं की स्थिति, चाहे वह केवल अदला- बदली हो... ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान अमेरिका को ईरान के बारे में खुफिया जानकारी दे रहा था। यह सब भी उसमें जुड़ जाता है कि ट्रंप के परिवार को भी क्या- क्या ऑफर किया गया है। अमेरिका और ट्रंप के परिवार को जो ऑफर किया गया है, वे दो अलग- अलग बातें हैं।

सी. राजा मोहन: विजया, क्या आप भारत- अमेरिका के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? संक्षेप में, और फिर...

के. पी. विजयालक्ष्मी: जी हाँ। मैं बस एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा या सरल विश्लेषण का प्रयोग करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इस सवाल में ट्रंप प्रशासन से निराशा के बारे में एक गुप्त शंका थी कि पहले साल में क्या हुआ आदि। मुझे लगता है कि यहीं मैं यह तर्क दूंगी कि यह एक ऐसा दौर है जो भारत के रणनीतिक सबक को दर्शाता है, इसे किसी और संदर्भ में नहीं डालना चाहिए।

दूसरा, मुझे लगता है कि भारत ने मामले को तूल नहीं दी। भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। उसने संयम से काम लिया। सबसे पहले, भारत ने संयम बरता। जो बात सच में ध्यान देने लायक थी, वह यह थी कि उसने बिना किसी सार्वजनिक टकराव के दबाव को झेला। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम कुछ कहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कहते। नहीं। हम दबाव झेल रहे हैं और यह महत्वपूर्ण बात है। दूसरा?

सी. राजा मोहन: देखिए, यही है गांधीगिरी। अहिंसक विरोध।

के. पी. विजयालक्ष्मी: क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं?

सी. राजा मोहन: जी हाँ, जल्दी से अपनी बात पूरी करें।

के. पी. विजयालक्ष्मी: जी, अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि हमने वाशिंगटन के साथ लगातार, भले ही मैं कहूँ कि चुनिंदा, जुड़ाव बनाए रखा है। इसलिए, मुझे लगता है कि भारत किसी भी कीमत पर समान दूरी या गठबंधन के बारे में विचार नहीं कर रहा है। वह रणनीतिक स्वायत्तता और बहुत ही शक्तिशाली, अस्थिर साझीदार के साथ काम करने की क्षमता का अभ्यास कर रहा है, बिना उस साझीदार की स्थिरता पर निर्भर हुए। मुझे लगता है कि यह सच में कुछ ऐसा है जो हमने सीखा है। धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद। अच्छा उत्तर था। तीन सवालों का अगला दौर शुरू करते हैं। मुझे पीछे, एक महिला नज़र आ रही हैं जो सवाल पूछना चाहती हैं। नहीं, उनसे पहले वाली। जी हाँ। महिलाओं को थोड़ी सी प्राथमिकता देते हैं।

अन्वेषा घोष: धन्यवाद सर। श्री पेरी, आपने अफ़गानिस्तान और बगराम के बारे में बात की। मेरा सवाल उसी से जुड़ा है। मैं. डॉ. अन्वेषा घोष हूँ, परिषद में फेलो हूँ। ट्रम्प के बगराम वापस लौटने के आइडिया में कितनी सच्चाई है, यह देखते हुए कि इसके लिए तालिबान की सहमति और निश्चित रूप से क्षेत्रीय समर्थन की ज़रूरत होगी और 2021 में जिस प्रकार से उन्होंने बगराम एयरबेस छोड़ा था, उस इतिहास को ध्यान में रखते हुए? धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: आपके ठीक पीछे, जी हाँ।

ज़ीशान अली: बहुत- बहुत धन्यवाद। मैं ज़ीशान हूँ और परिषद में शोध इंटर्न हूँ। मेरे सवाल का जवाब पैनल के कोई भी सदस्य दे सके हैं। डॉ. पंखुड़ी ने अपनी प्रस्तुति में बताया कि भारत 3.7% भागीदारी के साथ 10वें स्थान पर है लेकिन उस पर सबसे अधिक टैरिफ लगाया जा रहा है। ऐसा क्यों है, जब हम अमेरिका के साथ व्यापार घाटे में 10वें स्थान पर हैं, तब भी हमसे सबसे अधिक टैरिफ वसूला जा रहा है? तो यदि आप चाहें, तो क्या यह रूस की वजह से, मुझे नहीं पता। बस यही पूछना था।

सी. राजा मोहन: वहाँ से कोई सवाल पूछना चाहता है। कृपया अपना परिचय दें, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा।

सूर्यनाथ: नमस्कार, मेरा नाम सूर्यनारायण है, मैं जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध अध्येता हूँ। ट्रंप प्रशासन ने बीते 365 दिनों में बहुत कुछ किया है। मेरा सवाल प्रो. विजयालक्ष्मी मैम से है, क्या हम यह कह सकते हैं कि उन्हें पार्टी के साथ- साथ एमएजीए (MAGA) बेस में भी पूरा समर्थन मिल रहा है, जबकि उनके प्रशासन में अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन हुआ? यह ऐसे समय में हो रहा है जब रिपब्लिकन पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों को नियंत्रित कर रही है। धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद, जी हाँ। अफ़गानिस्तान से शुरू करते हैं।

दिनाकर पेरी: जी हाँ, अभी तक यह स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि बड़े पैमाने पर अफ़गानिस्तान में अमेरिका असल में क्या चाहता है। संकेत और अंदाज़े यही हैं कि यह एक सीमित भूमिका होगी, जैसे, केवल बगराम को सहयोग करना। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अफ़गानिस्तान या अफ़गान स्तान के अंदरूनी इलाकों में वापस जाने का इरादा रखता है। क्योंकि इससे बीते दो दशकों में जो कुछ हुआ है, वह सब बेकार हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई गुंजाइश है, किसी भी तरह से। न तो सैन्य रूप से, न ही राजनीतिक रूप से। फिर से, जिसमें राजनीति आती है, बहुत सारी चीज़ें, कोई रास्ता ही नहीं है। अधिक- से- अधिक बगराम, सामरिक कारणों से जैसे स्पेशल ऑप्स, सलाहकार आदि।

सी. राजा मोहन: भेदभाव वाले टैरिफ पर, आप कुछ कहना चाहेंगे?

पंखुड़ी गौर: हाँ, सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल मैंने बताया है कि भारत 37% का योगदान दे रहा है और फिर 50%, 50% टैरिफ, 25% प्लस 25%, 25% इस मायने में कि क्योंकि हम रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, इसलिए हम पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया जा रहा है, ठीक है? मूल रूप से, मैं यही कहना चाह रही थी। व्यापारा घाटा ही एकमात्र वजह नहीं है जिसकी वजह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं। कई सारी संभावित चीजें हैं, जैसे रूस के साथ व्यापार करना या दूसरे देशों के साथ व्यापार करना और साथ ही आप यह भी देखते हैं कि भारत, जब आप आव्रजन हिस्से या क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे सेवा क्षेत्र, भारत, अमेरिका में प्रमुख है।

तो व्यापार से संबंधित बहुत सारी चीजों को कम करने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए अलग- अलग, जैसे ज्यादा ट्रेड टैरिफ। बेशक, अलग- अलग टैरिफ के साथ।

सी. राजा मोहन: जी हाँ, मुझे लगता है, विजया, आप उस घरेलू सवाल पर टिप्पणी करना चाहती हैं जो पूछा गया था?

के. पी. विजयालक्ष्मी: जी हाँ, मुझे लगता है कि इसका जवाब देना ठीक रहेगा। केवल इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि भारत इस बात में कुछ दिलचस्पी दिखा रहा है कि देश में गठबंधन कैसे हैं। पहली बात, एमएजीए (MAGA) विश्व एक जैसा नहीं है। आपको समझना होगा कि वहाँ ट्रम्पलिकन हैं, रिपब्लिकन हैं, और एमएजीए (MAGA) भी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होगा और मैं इस सावल से बहुत खुश हूँ क्योंकि ग्रीनलैंड और वेनेजुएला के मुद्दे के बाद एक बड़ी बहस चल पड़ी है कि कुछ रिपब्लिकन, कुछ विशेष रिपब्लिकन, पार्टी छोड़ सकते हैं। इससे यह पता चलता है ...

सी. राजा मोहन: अच्छी बात है, माइकल, क्या आप घरेलू मुद्दे के सवाल पर कुछ कहना चाहेंगे?

के. पी. विजयालक्ष्मी: अतीत के संदर्भ में सत्ता का विस्तार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?

सी. राजा मोहन: मुझे लगता है कि हमारा संपर्क बार- बार आपसे टूट जा रहा है विजया। इसलिए यदि आप संक्षेप में अपनी बात पूरी करें तो अच्छा रहेगा। हम अब आपको सुन पा रहे हैं। कृपया संक्षेप में उत्तर दीजिएगा क्योंकि हमारा संपर्क बार- बार टूट रहा है।

के. पी. विजयालक्ष्मी: जी हाँ। अच्छी बात है, संपर्क टूटने के लिए माफी चाहती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, रिपब्लिकन एकजुटता का मुख्य स्रोत अब देखा जाना चाहिए, पहली बात, एमएजीए (MAGA) एक जैसा नहीं है। दूसरी बात, ट्रम्पलिकन हैं- रिपब्लिकन हैं, और एमएजीए (MAGA) है। तीसरी बात, दोनों सदनों पर नियंत्रण होने के बावजूद, उन सभी ने पहली बार रिएक्ट किया है, मुझे एमएजीए (MAGA)आधार में दरार दिख रही है। एक व्यक्ति है जिसका नाम मार्जोरी ग्रीन है, जिसने राष्ट्रपति से अलग रास्ता अपनाया है, जो बहुत वफादार समर्थक है। इसके अलावा, हम कुछ सीनेटर और कुछ हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स को देख रहे हैं। वास्तव में, स्पीकर ने ऑन- रिकॉर्ड कहा है कि ग्रीनलैंड में ज़मीन पर कोई सैनिक नहीं होगा, मेरे ख्याल से यह एक बड़ा परिवर्तन है। यह कोई ऐसी बात नहीं है और यह हमेशा के लिए नहीं है, फिर भी हर कोई राष्ट्रपति को समर्थन देगा।

सी. राजा मोहन: हाँ, हमें वह मिल गया। हाँ, माइकल, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि एमएजीए (MAGA) एक साथ रहेगा या टूट जाएगा?

माइकल कुगेलमैन: मैं असल में टैरिफ के बारे में सवाल पर बहुत जल्दी से एक बात कहना चाह रहा था। मुझे नहीं लगता कि एमएजीए(MAGA) कहीं भी जल्द ही जाने वाला है, लेकिन अमेरिका, मैं घरेलू राजनीति का विशेषज्ञ नहीं हूँ। टैरिफ के मुद्दे पर, मैं डॉ. गौर से पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरे कहने का यह मतलब है कि भारत पर 50% टैरिफ है, इसका एक बड़ा कारण रूस के साथ उसका कारोबार करना है। लेकिन यह बात भी ध्यान देने वाली है कि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि भारत के मुकाबले चीन रूस अधिक तेल आयात करता है, भारत पर टैरिफ अधिक क्यों लगाए गए? और यहाँ, मुझे लगता है कि आर्थिक दबाव के मुद्दे को देखना होगा। मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन यह मानता है कि चीन में ऐसे कदम उठाने की क्षमता है जिससे वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को वास्तव में नुकसान पहुँचा सकता है जैसा कि सज़ा देने वाले कदम या दूसरे तरह के कदम, जैसे कि अपनी आपूर्ति श्रृंखला और खनिजों तक पहुँच को बंद करना आदि।

जबकि वाशिंगटन में यह माना जाता है कि भारत के पास उस स्तर का आर्थिक दबदबा नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक और वजह है कि प्रशासन भारत पर उसके रूसी तेल आयात के लिए अधिक टैरिफ लगाने में सहज रहा होगा, लेकिन चीन पर नहीं। टैरिफ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ट्रंप काफी समय से भारत पर टैरिफ को लेकर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी कोई स्पष्ट वजह समझ नहीं आती है। मेरे कहने का अर्थ है, यदि आपको याद हो अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहा था और वे हार्ले- डेविडसन टैरिफ को लेकर परेशान थे, जो मुझे पता है कि अब हटा दिए गए हैं।

बगराम मुद्दे पर, मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत सी बातें कहते हैं, कभी- कभी यह जानना मुश्किल होता है कि वह किस बारे में सच में गंभीर हैं और किस बारे में नहीं। मुझे लगता है कि बगराम मुद्दे पर वह वास्तव में गंभीर नहीं थे। यदि कुछ था भी तो शायद उन्होंने सोचा होगा, यदि वह किसी समय इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे थे कि बगराम अमेरिका के लिए ईरान पर नज़र रखने के लिए बेहतर स्थिति में रहने का एक तरीका होगा। मैं काफी समय से सोच रहा था कि यदि उनके पास बगराम तक पहुँच या नियंत्रण रखने का कोई मूल कारण होता तो वे चीन के परमाणु या ऐसी किसी चीज़ पर नज़र रखने के लिए नहीं होता। वह ईरान पर नज़र रखने के लिए होता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई गंभीर बात है जो वे करना चाहते हैं। हमने हाल ही में उसे इस बारे में ज्यादा बात करते हुए नहीं सुना है, जो मुझे लगता है कि एक और संकेत है कि वह वाकई उसका कोई गंभीर लक्ष्य नहीं है, कम- से- कम वर्तमान समय में तो नहीं।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद। सवालों का एक और दौर, शायद। जी मैं आपको देख पा रहा हूँ, कृपया सवाल पूछें।

मलांचा चक्रवर्ती: नमस्कार, मेरा नाम मलांचा चक्रवर्ती है। मैं ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन से हूँ। आज बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है क्योंकि हमने टैरिफ और व्यापार घाटे के बारे में इतनी सारी बातें की हैं, मुझे लगता है कि हमें निवेश के पक्ष के बारे में भी थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। आप व्यापार खाते के साथ- साथ निवेश खाते में भी अधिशेष नहीं रख सकते। इसलिए, अमेरिका का परंपरागत रूप से हमेशा व्यापार घाटा बड़ा, बढ़ता रहा है क्योंकि उसके निवेश खाते का बहुत बड़ा हिस्सा अधिशेष का है।

यहीं पर अमेरिका की शक्ति नज़र आती है। डॉलर की वजह से। इस प्रकार का लाभ दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा क्यों करेंगे जिससे यह शक्ति कम हो जाए। मेरे कहने का मतलब है, उन्हें व्यापार घाटे की चिंता क्यों है? क्योंकि टैरिफ से निवेशक दूर नहीं भागेंगे। मेरे कहने का मतलब है, यदि हम इस बारे में थोड़े सोचें तो मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी।

आयुष जोशी: नमस्कार सर। मेरा नाम आयुष जोशी है और मैं भारतीय वैश्विक परिषद में शोध इंटर्न हूँ। मेरा सवाल पंखुड़ी मैम से है। जैसा कि आपने अपनी प्रस्तुति में बताया है, संरक्षणवाद की विचारधारा की वजह से गैर अमेरिकी व्यापार संरचना के लिए

माहौल बन रहा है। कई रीजनल एफटीए हो रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ- भारत एफटीए भी चल रहा है। हाल ही में यूरोपीय संघ- भारत एफटीए भी चल रहा है। साथ ही, अभी यूरोपीय संघ- मार्कुस या एक मुक्त व्यापार समझौता किया गया था। मेरा सवाल यह है कि इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि उपभोक्ता पर कीमतें बढ़ने का रुझान दिख रहा है। प्राथमिक उद्देश्य व्यापार घाटे को कम करना था, लेकिन आपसी टैरिफ की वजह से व्यापार घाटा भी कम नहीं हो रहा है। क्या यह विकर्षण प्रभाव, वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका के व्यापार उत्तोलन को कम कर देगा?

सी. राजा मोहन: अच्छी बात है। धन्यवाद। कोई और? जी हाँ, कृपया।

कशिश: नमस्कार। मैं जेएनयू के यू.एस. स्टडीज़ से कशिश हूँ। मेरा सवाल दिनाकर सर से है। आपने बताया कि वायु सेना के पास बहुत सारे... 40% में अमेरिकी इंजन होंगे। लेकिन यदि इस बारे में सोचें तो इतने सारे टैरिफ लगाने और ट्रंप के पीछे न हटने से क्या टकराव पैदा नहीं होगा, भले ही इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता हो? जैसा कि अमेरिका अपने F-35 को बेचना चाहता है, तो यह समझदारी वाली बात नहीं लगती कि पहले झगड़ा किया जाए और फिर अच्छा बनने की कोशिश की जाए, ऐसे में तो ग्राहक ही चला जाएगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं?

सी. राजा मोहन: मैंने उसी पंक्ति में हाथ देखा है, दूसरी तरफ से। जी हाँ।

वैष्णवी: बहुत- बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं जियोज्यूरिस्ट फेलो हूँ। मेरा पहला सवाल यह है कि, जैसा कि माइकल ने बताया, वेनेजुएला में ट्रंप का रणनीतिक हित क्या है? और दूसरा, अमेरिका की गलतियों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? जैसे, अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगा सकता है, अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगा सकता है, अमेरिका यूक्रेन या किसी और देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन यदि हमने संयुक्त राष्ट्र की नाकामियों और बाकी सब देखा है तो अमेरिका की गलतियों के लिए कौन उत्तरदायी है? और यही सवाल आपके लिए है।

सी. राजा मोहन: केवल अमेरिकी घरेलू राजनीति है। जी हाँ। शायद हमारे पास यहाँ कई सवाल थे। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि कोई और है जो सवाल पूछना चाहता है? आखिर में, हम इस दौर के बाद आज के सत्र को समाप्त करेंगे। जी हाँ, कृपया। फिर मैं वक्ताओं को थोड़ा समय दूँगा कि वे आखिर में हम सबसे कुछ साझा करना चाहें तो...

दिप्रिया घोष: नमस्कार सर। मैं पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय से दिप्रिया घोष हूँ। मेरा सवाल डॉ. माइकल कुगेलमैन से है। अभियान का नाम ही 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' है, लेकिन अमेरिकी नागर समाज में विरोध और असंतोष बढ़ रहा है। मेरा सवाल यह है कि ज़मीनी राजनीति और अमेरिकी नागर समाज का ट्रंप की नीतियों के बारे में क्या नज़रिया है?

सी. राजा मोहन: धन्यवाद। मैंने देखा, आखिर में एक हाथ उठा था। जी हाँ, सवाल को संक्षिप्त रखें। क्योंकि हम सत्र के आखिरी चरण में हैं।

त्रिवेदी जल: पैनल के सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं टाइसवर्स फाउंडेशन से त्रिवेदी जल हूँ। मेरा सवाल पैनल के सदस्यों से यह है कि, सीरिया में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, जहाँ ट्रांजिशनल सरकार ने उत्तर- पूर्वी सीरिया की ओर हमला किया है, हमने एसडीएफ की तेज़ी से वापसी देखी है, तो क्या यह इस बात का संकेत देता है कि वाशिंगटन ने एसडीएफ को छोड़ दिया है और एसडीजी (SDF) को एक वैकल्पिक विकल्प के रूप पर देख रहा है? धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: ठीक है, मुझे लगता है कि क्या यहाँ कोई और है? कृपया जल्दी से अपना सवाल पूछें।

प्रीति: नमस्कार, मैं प्रीति हूँ। जैसा कि हम राष्ट्रपति श्रीमान ट्रंप के अप्रत्याशित स्वभाव के बारे में सुन रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या श्रीमान ट्रंप का यह अप्रत्याशित स्वभाव अमेरिकी विदेश नीति या पूरे अमेरिका को कोई लाभ पहुंचा रहा है या हम यह पूछ सकते हैं कि यह अमेरिका की सबसे शक्तिशाली देश की छवि बनाए रखने में कितना मदद कर रहा है?

सी. राजा मोहन: अच्छी बात है। हमें अंतिम दौर के सवाल मिल गए हैं और मुझे लगता है कि हमें विजया से शुरू करना चाहिए, क्या आप पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब संक्षेप में देना चाहेंगी? आपको सभी सवालों के जवाब नहीं देने। विजया, क्या आप सुन रही हैं? अच्छा, पंखुड़ी क्या आप शुरू करना चाहेंगी, अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए थे।

पंखुड़ी गौर: टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हाल ही में कुछ अनुमान लगाए गए हैं, बेशक ये शुरुआती अनुमान हैं लेकिन अभी भी इस पर गहन शोध की आवश्यकता है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, विश्व के किन- किन ज़रूरी देशों पर और कितने टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इस हिसाब से वैश्विक व्यापार में लगभग 5.5% से 8.5% तक की कमी आ सकती है।

दूसरी बात, इससे केवल वैश्विक व्यापार ही प्रभावित नहीं होगा, बल्कि वैश्विक जीडीपी पर भी प्रभाव पड़ेगा, अनुमान है कि मध्यावधि में इसमें लगभग 2% की कमी आएगी और यह केवल विश्व भर में ही नहीं, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी होगा। हमने देखा है कि महंगाई बढ़ रही है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, विशेषरूप से अलग- अलग उत्पाद हैं, जहाँ उपभोक्ता की आवश्यकता के हिसाब से मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए टैरिफ बढ़ने की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी आर्थिक प्रभाव पड़ा है।

निश्चित रूप से, निवेश बनाम व्यापार के मुद्दे पर, जिसका आपने ज़िक्र किया, निवेश तो ज़रूर, लेकिन जब आप व्यापार पर ध्यान दे रहे थे, तो यह वास्तव में व्यापार घाटे की वजह से है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में रोज़गार पर असर डाल रहा है और वहाँ के किसानों या निर्माताओं को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए लक्ष्य तो हैं लेकिन निवेश एक आउटवर्ड एफडीआई देश होने के नाते, यानी कई देशों में निवेश करने के बावजूद, देश में नियमों और कानूनों की कम पूर्वानुमान के कारण, अमेरिका का आउटवर्ड निवेश भी कई देशों पर प्रभाव डार रहा है और निवेशकों... यानि देशों में... वे उस हिसाब से इसे पूरी तरह से प्रदान नहीं कर रहे हैं।

सी. राजा मोहन: कोई आखिरी बात जिसे आप संक्षेप में बताना चाहें। यह आपका आखिरी मौका होगा।

पंखुड़ी गौर: अच्छी बात है सर। मुख्य रूप से भारत के पास यह विकल्प है, हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हम इसे ऐसे कह सकते हैं... अमेरिका पर भी टैरिफ लगा सकते हैं लेकिन जैसा कि प्रोफेसर विजयालक्ष्मी मैम ने कहा कि हम स्वयं को रोक रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं कि और हम इस पर काम कर रहे हैं कि सबसे अच्छे हालात में हम क्या कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में जब सरकार बदले तो हम उस स्थिति में अधिक सुरक्षित रहें।

दिनाकर पेरी: बस एक छोटा फॉलो- ऑन प्वाइंट, वे पहले से ही लोगों से बात कर रहे हैं। अमेरिका में बढ़ती कीमतें और घरेलू राजनीति, यदि आप वहाँ लोगों से बात करते हैं, पहले से ही यह भावना है कि कुछ सेक्शन, कुछ सेगमेंट में कीमतें बढ़ रही हैं, आप बस लोगों से बात करें, आपको यह पता लग जाएगा। दूसरा, भारतीयों पर इसका जो प्रभाव पड़ा है, यदि आप वहां के लोगों से बात करेंगे तो, मेरे बहुत सारे दोस्त और परिवार के लोग वहाँ हैं, एक आम भावना नज़र आएगी, उन्होंने लंबे समय से महसूस नहीं किया है कि उन्हें खिलाफ अमेरिकियों के दिल में नफ़रत है।

दूसरी तरफ, यदि आप देखें तो पिछले साल के बीच में अमेरिका में एक सर्वेक्षण किया गया था, मैंने उसे एक पब्लिकेशन में पढ़ा था, सर्वेक्षण में अलग- अलग आप्रवासियों को शामिल किया गया था और जानने की कोशिश थी कि वे अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देते हैं या अर्थव्यवस्था से कितना लेते हैं। ऐसे देशों की सूची लंबी है जो असल में जितना देते हैं उससे अधिक लेते हैं, लेकिन जो देश को वापस देते हैं उनमें भारतीय सबसे ऊपर हैं। तो यह कुछ थोड़ी सी बात है... आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि भारतीयों को अप्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। यह बीच- बीच का कुछ मामला जैसा है।

F35 के सवाल पर या क्या आप ग्राहकों को डरा रहे हैं। देखिए, रक्षा में काम करने वाली निर्भरता से चक्र बहुत लंबे होते हैं, यानि, आप दशकों, चार दशकों, पांच दशकों की बात कर रहे होते हैं। निर्भरता यह केवल आधी बात नहीं है, यह गोल- गोल घूमती है, यह प्रत्यक्ष नहीं है। कोई मूल्य नहीं है, एक कारण है और उसका प्रभाव पड़ता है। कोई दूसरी चीज़ आपको कहीं और प्रभावित करती है। फिर, चक्र प्लेटफॉर्म के मामले में नहीं होता है, माने, यह बहुत मामूली हो सकता है, आपके अतिरिक्त कल- पुर्जे, रख-रखाव, समर्थन या डिलीवरी में देरी जैसी छोटी- मोटी बातें।

उदाहरण के लिए, अपाचे में देरी हुई लेकिन अमेरिका ने इसे रोक दिया, उसने किसी और चीज़ को प्राथमिकता दी, इसे कुछ वर्षों के बाद डिलीवर किया गया क्योंकि असल में मुझे लगता है कि यदि मुझे सही याद है तो यह 8वें या 10वें नंबर पर था। जैसे, हमें यह सभी उच्चतम स्तरों पर दखल के बाद मिला, जैसा कि छह क्षेत्रों के नीचे बताया गा है। यहाँ तक कि इंजन में भी देरी हुई, मेरा मतलब है, यह अधिकतर आपूर्ति श्रृंखला की वजह से है, बात यह है कि देरी तो हुई है। इसलिए भारत ने बीते दशक में तकनीक देने से इनकार और प्रगति में रुकावटें बहुत झेली हैं। इसलिए हम जानते हैं कि हमने इसका सामना किया है, मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसा होगा लेकिन बात यह है कि निर्भरता हमेशा रहती है, यह हमेशा आपकी गर्दन पर लटकी तलवार की तरह होती है।

सी. राजा मोहन: विजया, क्या आप कनेक्टेड हैं? क्या आप कोई आखिरी विचार साझा करना चाहती हैं?

के. पी. विजयालक्ष्मी: जी हाँ, यदि मैं कर सकती हूँ तो कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। अच्छा। मैं बस ट्रंप 2.0 के व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि यह उन सवालों में से एक था जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। पहली बात यह है, राजा, इसके बारे में विचार करें। सहयोगी अब ज़िम्मेदारी को अंदर से महसूस कर रहे हैं। बस पूरी तस्वीर देखें और मुझे लगता है कि यह एक विश्लेषण का बिन्दु है जिसे बताने की ज़रूरत है, नाटो (NATO) आदि। लेकिन केवल बचाव करने और विश्वास बनाए रखने या प्रबंध करने की बजाय, मुझे लगता है कि वे ज़िम्मेदारी को भीतर से महसूस कर रहे हैं।

दूसरा, मुझे लगता है कि शत्रु आमने- सामने की जंग की बजाय जांच- पड़ताल कर रहे हैं। राजा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस समय मेरा यही विचार है क्योंकि सीमाओं को परखा जा रहा है, चाहे वह ताइवान हो, यूक्रेन हो, या ईरान भी, कि क्या वहाँ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं लेकिन असल टकराव से अधिक जांच- पड़ताल हो रही है। यह एक दिलचस्प बात है।

टकराव वाले इलाकों में भी अस्थिरता है। हालांकि रोक अभी भी है, लेकिन संकट का प्रबंधन अधिक कठिन हो गया है क्योंकि वादे सशर्त लगते हैं और संकेत बहुत ज्यादा विपरीत हैं। मुझे लगता है कि यह ट्रंप 2.0 का प्रणालीगत प्रभाव है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसका मुख्य कारण विचारधारा है। इसने पहले से ही बचाव की तैयारी करवा दी है। साथ ही, मैं कहूँगा कि यह वैचारिक रुकावट ट्रंप के बाद भी बनी रहेगी। इसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए।

क्योंकि मुझे लगता है कि अगली सरकारें, मैं बस यहीं पर संक्षेप में बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूँगी, क्योंकि घरेलू स्तर पर, अगली सरकारें चाहे वह ट्रंप का तीसरा कार्यकाल ही क्यों न हो, मैं इस समय यह कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन हमें सीमाओं का सामना करना पड़ेगा, मुख्य रूप से केवल सहयोगियों या संस्थानों से नहीं, क्योंकि यह स्पष्ट रूप पर ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वे नियंत्रित कर सकें बल्कि देश में घरेलू राजनीतिक गठबंधनों से ऐसा संभव है। हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए और इसी को समझने एवं ध्यान में रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद विजया। आखिर में अपने बहुमूल्य विचारों को साझा करने के लिए। माइकल, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बोलने का मौका दूँ, मैं आज अपने दर्शकों को देख कर बहुत हैरान हूँ, बहुत से युवा आज इस सत्र का हिस्सा बनने आए हैं। लेकिन किसी ने भी आपसे चीन और जी2 (G2) के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। हमें थोड़ा बताएं कि अमेरिका और चीन के बीच क्या हो रहा है। क्या भारत को परेशान होना चाहिए या भारत को इसे ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए? आप इसे अपने दूसरे बातों में भी शामिल कर सकते हैं, जो अब तक सामने आई हैं।

माइकल कुगेलमैन: धन्यवाद। असल में, मैं चीन की बात करने वाला था क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया मैं दक्षिण एशिया में ट्रंप के रणनीतिक हित के बारे में सवाल का जवाब देने वाला था। वास्तव में रणनीतिक हित के नज़रिए से वे नहीं विचार करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दक्षिण एशिया में उनका बहुत अधिक रणनीतिक हित है। हालाँकि मुझे लगता है कि विशेषरूप से आर्थिक क्षेत्र में वे अभी भी चीन के साथ जबरदस्त मुकाबला करना चाहते हैं। मेरे विचार से यह अमेरिकी सरकार के एक आवश्यक साधन के बारे में उनके विचारों और उनके प्रशासन के विचारों के बारे में कुछ बता सकता है, जिसे कई वर्ष पहले शुरू किया गया था यानी अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम, जिसका उद्देश्य निवेश के माध्यम से हिंद- प्रशांत में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाना है और स्पष्ट रूप से इसका उद्देश्य चीन का मुकाबला करना है।

महत्वपूर्ण खनिज अब बीएफसी (BFC) के काम का एक बड़ा हिस्सा है इसलिए मुझे लगता है कि ट्रंप और उनका प्रशासन बीएफसी की गतिविधियों को बढ़ाना चाहेंगे। बीएफसी भारत में बहुत सक्रिए रहा है लेकिन दक्षिण एशिया के दूसरे स्थानों पर उतना सक्रिए नहीं हो पाया। मज़दूरों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं की वजह से यह बांग्लादेश में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में भी इसकी उपस्थिति व्यापक स्तर पर नहीं है। लेकिन मेरे विचार से बीएफसी एक ऐसा ज़रिया हो सकता है जिसका इस्तेमाल वह और उनका प्रशासन कर सकता है, यह मानते हुए कि चीन के साथ मुकाबला करने की इच्छा बनी रहेगी, जो मुझे लगता है कि रहेगी। लेकिन जैसा कि हमने ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से देखा, ऐसा लगता है कि चीन के प्रति थोड़ नरम रवैया अपनाने की इच्छा है, जैसा कि हमने बाइडेन, ट्रंप 1.0 और यहाँ तक कि ओबामा के समय में देखा था।

मैं इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा। यदि हम इस बात के संकेत ढूंढ़ रहे हैं कि ट्रंप के दूसरे साल में दक्षिण एशिया में अमेरिकी नीति कैसी होगी, तो नई दिल्ली में हमारे नए कर्मी, भारत में नए अमेरिकी राजदूत, सर्गियो ग़ोर पर नज़र रखें। वह ट्रंप के बहुत करीब हैं। वह वाशिंगटन में बड़ा कद रखते हैं और उनके पास दो- दो ज़िम्मेदारियाँ हैं, केवल भारत में राजदूत ही नहीं हैं, बल्कि अमेरिका दक्षिण एशिया राजदूत भी, यह एक ऐसा पद है जो अमेरिकी सरकार में पहले कभी नहीं रहा। उन्हें स्पष्ट रूप पर बहुत कुछ करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, मुझे लगता है कि वह जो करेंगे, उससे इस बात का अच्छा अंदाज़ा लगेगा कि दक्षिण एशिया के मामले में राष्ट्रपति किस तरफ जाएंगे, यह देखते हुए कि ये दोनों आदमी कितने करीब हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि गोर ने कुछ बहुत ही दिलचस्प बैठकें की हैं।

उन्होंने बांग्लादेश के पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बात की, जैसा कि मुझे लगता है। कुछ ही सप्ताह में चुनाव होने वाले हैं लेकिन उन्होंने दक्षिण एशियाई नेताओं के साथ ऐसे स्तर पर बातचीत की है जिसकी मुझे आशा नहीं थी। यह देखना

दिलचस्प होगा कि भारत में अमेरिकी राजदूत न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए अपने नज़रिए से क्या करते हैं। धन्यवाद।

सी. राजा मोहन: धन्यवाद माइकल। इस सत्र का समापन करते हुए मुझे वास्तव में प्रसन्नता हो रही है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि आखिर में कुछ बातों को कहते हुए, मैं घटनाक्रम को संक्षिप्त रूप देना का प्रयास नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ मुद्दे सामने आए हैं, उन पर बात करना ज़रूरी। पहला, व्यापार का मुद्दा, जो अब भारत और अमेरिका के बीच परेशानी की मुख्य वजह बन गया है। मेरे विचार में भेदभाव, वास्तविक राजनीतिक सच्चाई है। पर इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए केवल यह शिकायत करना कि यह भेदभाव है जो कि बढ़ावा देने, प्रोपेगेंडा करने या यदि आप चाहें तो सहानुभूति जुटाने के लिए अच्छा है।

लेकिन सच तो यह है कि ट्रंप ने असल में जीएटीटी- डब्ल्यूटीओ (GATT-WTO) व्यवस्था के मूल सिद्धांत को ही कमज़ोर कर दिया है, जिसके अनुसार आप व्यापार साझीदारों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। खैर, यदि आप शुरूआत से देखें तो ट्रंप की नीति में शेष विश्व के खिलाफ टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात थी। वह भी एक जैसे आधार पर नहीं बल्कि अलग-अलग देश के लिए अलग- अलग टैरिफ। मुझे लगता है कि वह अपनी बात पर कायम रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे- समझे यह बात कही थी। आज फ्रेंच लोग निशाने पर हैं। अरे, तुम मेरी आलोचना कर रहे हो, तुम्हारे वाइन पर मैं 200% का टैरिफ लगा दूं?

यह रवैया है, यही मूल तरीका है। अब आप कह सकते हैं कि यह अच्छा है, बुरा है, खराब है, जो भी है, लेकिन सच यह है कि वह इसी प्रकार की नीति अपना रहे हैं। इसके मूल में, मेरे विचार से हमें यह पहचानना होगा कि अमेरिका ने अपने व्यापार घाटे को एक शक्ति में बदल लिया है। यानी, चूँकि दुनिया के अधिकांश देशों के पास अमेरिका को निर्यात करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो अमेरिका वैश्विक निर्यात का हौद है। चीन निर्यात तो करता है लेकिन अधिक आयात नहीं करता। इसलिए, आप कुछ भी करें, हमारे चुप रहने का एक कारण यह है कि आपका निर्यात, आपका अधिकांश निर्यात अमेरिका को होता है। केवल 80 अरब डॉलर का सामान। हम रूस को 5 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं, चीन को 10-12 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करते हैं। बस इतना ही।

तो आप रणनीतिक स्वायत्ता पर जो चाहें कर सकते हैं, आप बहुध्रुवीयता की बात कर सकते हैं आप ब्रिक्स (BRICs) की बात कर सकते हैं लेकिन आपका मुख्य निर्यात अमेरिका को ही हो रहा है। इसलिए आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? यह एक नीतिगत चुनौती है, केवल एक कहने वाली बात भर नहीं। यह तब लाभकारी होता है जब हम जैसे लोगों को उचित अकादमिक कार्यों के लिए पैसे मिलते हैं और हम सभी पत्रकार, मीडिया संपादक हैं। लेकिन एक नीति बाने वाले के लिए सच्चाई यह है कि जब आप व्यापार घाटे की बात करते हैं, तो मेरे गृह राज्य आंध्र प्रदेश के झींगा किसान हैं, तिरुपुर के कपड़ा श्रमिक हैं, सूरत के हीरा व्यापारी हैं, उनके साथ क्या होता है?

आप इस अचानक मिले झटके से कैसे उबरेंगे जो एक ऐसे देश से मिला है जो अब एक तरह से बेकाबू लग रहा है और अपने बाज़ार को हथियार के रूप में प्रयोग करने को तैयार है? तो हमें इससे निपटना होगा, यह पहले कभी नहीं हुआ, यह उससे अलग है जिसका सामना हमें पहले अमेरिका के साथ करना पड़ा है और इससे निपटना होगा। दूसरा, मेरे विचार में आव्रजन के सवाल पर। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं भी आंध्रप्रदेश से हूँ और हममें से बहुत से लोग अमेरिका में हैं लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका में विदेशी आव्रजन की हर लहर को किसी- न- किसी दुश्मनी का सामना करना पड़ा है।

आयरिश लोगों की बात पर लौटें तो बहुत समय तक आयरिश लोगों को गोरा नहीं माना जाता था। उन्हें विदेशी माना जाता था, वे कैथोलिक थे। वास्प्स की ज़मीन पर, आयरिश लोगों को बहुत समय तक स्वीकार नहीं किया गया था। यह समस्या यहूदियों

और इतावलियों के साथ भी थी। एक प्रकार से, अमेरिका का तर्क, उसका पूंजीवाद, पूंजीवाद के लिए मौजूद बड़ी संभावनाओं से निपटने के लिए विदेशी मज़दूरों की आवश्यकता है, लेकिन, सामाजिक रूप से आप जो आयात करते हैं, जैसे कि एक प्रतिभागी ने कहा, आप श्रमिकों का आयात करते हैं, इससे मज़दूरों को मिलने वाले वेतन में कमी आती है और सामाजिक रूप से दूसरे प्रभाव भी पड़ते हैं। सामाजिक दबाव के बारे में सवाल पैदा होते हैं। क्या अमेरिका गोरों का देश है? क्या यह ईसाई राष्ट्र है? आज ये मुद्दे, जैसे- जैसे गैर- गोरी आबादी बढ़ी है, जैसे- जैसे बाहरी आबादी बढ़ी है, सामाजिक रूप से बदलते संतुलन का सवाल एक मुद्दा बन गया है।

अब, ट्रंप स्वयं इन दोनों के बीच झूल रहे हैं। सिलिकॉन वैली में टेक प्रोफेशनल्स आंध्रा में रह रहे अपने संबंधियों को काम पर बुलाना चाहते हैं लेकिन जैसा कि आपने टेक्सास और कैलिफ़ोर्निया में देखा, लोग कह रहे हैं, नहीं, इनकी आबादी बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है कि यह एक तनाव है कि कॉर्पोरेट तार्किक आव्रजन चाहता है जबकि सोशल तर्क कहता है कि वे बहुत अधिक हैं और मुझे लगता है कि यह तनाव जारी रहेगा। लेकिन यह ऐसी बहस नहीं है जिसे हम प्रभावित कर सकें। यह अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका के नागर समाज का अंदरूनी बहस है। यह मामला कैसे सुलझता है, इसके हम बस देख ही सकते हैं। हम इसे चुनौती नहीं देंगे या इस पर बहस नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे देश में जा कर बसने का कोई अधिकार नहीं है।

हैदराबाद और विजयवाड़ा में रहने वाले मेरे संबंधियों के विपरीत, मैं यह सोचता था कि क्या इंजीनियरिंग की डिग्री अमेरिका जाने का अधिकार दिला देती है? ओह, भगवान, वे हमें आने से रोक रहे हैं। उनकी ये मज़ाल? लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय वीज़ा पाना कितना मुश्किल है? यदि आपको यह पता है, तो हम यह देख सकते हैं कि किसी देश का संप्रभु अधिकार है कि वह इस बात का फैसला करे कि किसे उसके देश में आना है और किसे नहीं। लेकिन जो लोग आव्रजन चाहते हैं, उनके बीच अंदरूनी टकराव की वजह से कोई फायदा नहीं होता, वे किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जो लोग इसके नतीजों से डरते हैं, मुझे लगता है कि यह एक तनाव है जो बना रहेगा।

तीसरा, मुझे लगता है कि हमने बहुपक्षता के बारे में अधिक बात नहीं की। चाहे हम डब्ल्यूटीओ की बात करें, चाहे आज हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें, हम पाएंगे कि ग्लोबल बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर कल क्या करने वाला है। वास्तव में यह बहुत ही नाटकीय पल है। मेरे कहने का अर्थ है, इतने वर्षों से हमने संयुक्त राष्ट्र में जॉर्ज बुश को देखा है या संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप के प्रथम कार्यकाल को। संयुक्त राष्ट्र की बुराई करना रिपब्लिकन परंपरा का हिस्सा थी। लेकिन किसी ने भी इस प्रशासन से ऐसा करने की आशा नहीं की थी। ऐसा लगता है कि शांति और सुरक्षा के लिए एक समानांतर संरचना बनाया जाएगा। भारतीय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने के लिए बहुत उत्सुक हैं।

संभव है कि यह आपके लिए एक अरब डॉलर देकर बोर्ड ऑफ पीस में स्थान पक्का करने का मौका हो। मैं बस मज़ाक कर रहा हूँ। वास्तव में उसने एक चार्टर बनाया है जिस पर वह लोगों से हस्ताक्षर करने को कह रहा है। देखते हैं, गुरुवार को जब वे ऐसा करेंगे तो कितने देश इस पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बड़ा बदलाव है। मेरे विचार से यहाँ आपको याद रखना होगा, इसके लिए आदेश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सर्वसम्मत प्रस्ताव से आया है। 2803 नवंबर 2025 में पास हुआ था। चीन और रूस के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे, उन्होंने मतदान नहीं किया था।

तथाकथित ग्लोबल साउथ, तथाकथित यूरोपीय लोग बहुपक्षवाद के बड़े खिलाड़ी थे। मुस्लिम देशों, सबने इसके लिए मतदान किया, गाज़ा में शांति ढांचा बनाने के लिए, जिसे डोनाल्ड ट्रंप का एक आदमी चलाएगा। लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में असाधारण बात है कि आप किसी विवाद को सुलझाने की ज़िम्मेदारी एक व्यक्ति को सौंप देते हैं और कोई उस पर आपत्ति नहीं करता। आप यह तर्क दे सकते हैं कि देखिए, यहाँ सभी नियमों का उल्लंघन हो रहा है.... वास्तव में आप अभी उसे थोड़ी सी छूट देंगे लेकिन वे इसका बहुत अधिक फायदा उठा सकते हैं। हमें नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि बात यही है। मेरी राय में, असली बहस की

यह शुरुआत भर है, वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, उनका क्या होता है। मुझे लगता है कि भारत को भी इस पर ध्यान देना होगा।

चीन के बारे में, मैं कहूंगा कि ट्रंप जी2 (G2) की बात करते हैं, लेकिन जैसा कि माइकल ने कहा, चीन ने जितने प्रतिबंध लगाए हैं, उनमें से कुछ हटा रहा है, कुछ लगा रहा है। एक दिन आता है जब वह ताइवान का बचाव नहीं करता दिखता है, फिर अगले ही दिन वह ताइवान को हथियार बेच रहा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि चीन और अमेरिका के बीच के विरोधाभास खत्म नहीं हुए हैं और मेरे विचार से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इनमें से कुछ विरोधाभास बना रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इन दोनों के प्रति हमारी नीति इस बात पर आधारित होनी चाहिए कि उन दोनों के बीच क्या होता है। इसलिए, मेरे विचार से हमें दोनों शक्तियों के साथ अलग- अलग तरीकों से जुड़ने की अपनी समग्र नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। चीन के साथ हमारी समस्याएं अमेरिका के साथ हमारी समस्याओं से अधिक हैं लेकिन सवाल यह है कि चीन या अमेरिका के प्रति हमारी नीति अमेरिका और चीन के बीच टकराव या अच्छे संबंधों पर आधारित नहीं हो सकती बल्कि हमारी स्वतंत्र नीति होनी चाहिए।

आखिर में, पाकिस्तान के बारे में, मैं कहूंगा, आप जानते हैं, सबको लगता है कि कुछ बड़ा हुआ है लेकिन पाकिस्तान अभी भी 25वें आईएमएफ (IMF) प्रोग्राम के अधीन है, उसका जीडीप 400 अरब डॉलर पर अटका हुआ है। आप कह सकते हैं कि ट्रंप उन्हें कितना महत्व देंगे। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए जूझ रहा है। मेरे विचार से यह एक सच्चाई है कि ईरान जैसा एक देश है जहाँ 20 वर्षों में प्रति व्यक्ति आमदनी कम हुई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, वह बहुत ही चौंकाने वाला है। उसने अपनी सेना का प्रयोग विशेष लाभ उठाने के लिए किया है, पता नहीं इस बार यह अमेरिकियों के साथ काम करेगा या नहीं लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम बीते 80 वर्षों से देखते आ रहे हैं।

मध्य पूर्व गठबंधनों (मिडिल ईस्ट पैक्ट्स) की बात करें तो बगदाद गठबंधन (पैक्ट) क्या है? सेंट्रल कमांड- पाकिस्तान का संबंध कैसा था? यह कोई नई बात नहीं है। वास्तव में, मध्य पूर्व के लिए पाकिस्तान का भू- राजनीतिक महत्व कभी खत्म नहीं हुआ। अब आप एक प्रकार से इसकी वापसी देख रहे हैं लेकिन बीते चार- पांच बार में से किसी भी बार यह काम नहीं आया। आखिर में, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर उसे छोड़ दिया गया, क्या इस बार भी यही कहानी दुहराई जाएगी या कुछ अलग होगा? वक्त बताएगा।

आखिर में, मैं कहूंगा कि दक्षिण एशिया में, मेरे विचार से हमारे लिए अपना काम स्वयं करना अच्छा है। ट्रंप भारत को दक्षिण एशिया में और अधिक काम करने से नहीं रोक रहे हैं। इसलिए, हम देख रहे हैं कि चीन की मौजूदगी बढ़ रही है, मध्य पूर्व के देशों का दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए, मेरे विचार से हमारे लिए सवाल यह है कि हमारी अपनी दक्षिण एशियाई रणनीति क्या है? और मुझे लगता है कि इसे अमेरिका के नज़रिए या चीन के नज़रिए से देखने की बजाय, दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, मेरे विचार से यह सबसे अधिक ज़रूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि भारत के लिए अब अंदरूनी मामलों पर ध्यान देने का समय आ चुका है। यानि बाहरी दुनिया में उथल- पुथल मची है।

ट्रंप ने पहले कभी न देखी गई अनिश्चितता पैदा कर दी है। ऐसे कई परिवर्ती कारक हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन एक परिवर्ती कारक जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, वह है आपकी अपनी अंदरूनी सुधार की रणनीति और हम पहले ही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ सुधार कर रहे हैं। हम बजट का इंतज़ार करेंगे यह देखने के लिए क्या और सुधार होंगे। अपने अंदरूनी ढांचे बदलें, अपने अंदरूनी ढांचे को आधुनिक बनाएं, जिससे मुश्किल विश्व से निपटने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, मुझे लगता है कि ज्यादातर मध्यम शक्ति वाले देश यही करने वाले हैं और भारत भी यही कह रहा है कि वह ऐसा करेगा।

इसलिए, मुझे लगता है कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए, भारत के पास बहुत शक्ति है, बहुत मौका है। मैं कहूंगा कि सावधान रहें और हमारे सामने आने वाले बड़े तूफ़ान का सामना करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमें आमंत्रित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए को धन्यवाद। पैनल के सदस्यों का भी बहुत- बहुत धन्यवाद।

अज्ञात वक्ता: धन्यवाद सर। मुझे अध्यक्ष महोदय और पैनल के सदस्यों को धन्यवाद कहना है। आज दोपहर एक मंच पर आकर ऐसे विषय पर सबने अपने विचार साझा किए जिसमें स्पष्ट रूप से बहुत लोगों की दिलचस्पी है। मैं हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद देता हूँ। आप सब कृपया जलपान के लिए प्रस्थान करें। बहुत- बहुत धन्यवाद।